कमल संदेश
ikf{kd if=dk

संपादक

प्रभात झा, सांसद

कार्यकारी संपादक

डॉ. शिवशक्ति बक्सी

संपादक मंडल

सत्यपाल
संजीव कुमार सिन्हा

कला संपादक

धर्मेन्द्र कौशल
विकास सैनी

सदस्यता शुल्क

वार्षिक : 100/-
त्रि वार्षिक : 250/-

संपर्क

InL;rk : +91(11) 23005798
Qku (dk-) : +91(11) 23381428
QDl : +91(11) 23387887
पता : डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी–66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली–110003

ई–मेल
kamalsandesh@yahoo.co.in

प्रकाशक एवं मुद्रक : डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, के लिए एक्सेलप्रिंट, सी–36, एफ.एफ. कॉम्पलेक्स, झण्डेवालान, नई दिल्ली–55 से मुद्रित करा के, डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी–66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली–110003 से प्रकाशित किया गया। सम्पादक – प्रभात झा

विषय-सूची

महंगाई के विरोध में देशव्यापी 'जेल भरो आन्दोलन' के दौरान नागपुर में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी कार्यकर्ताओं को सम्बोधित करते हुए।

जेल भरो आन्दोलन

महंगाई के विरोध में देशव्यापी 'जेल भरो आन्दोलन'.................. 7

लेख

अमर शहीद डॉ. श्यामा प्रसाद मुकर्जी को प्रणाम!
&ykyÑ".k vkMok.kh.. 13

राष्ट्रपति चुनाव 2012
&vEck pj.k of'k"B.. 16

समस्या सुलझाने की बजाय और उलझाने का प्रयास
&lath d|ekj flUgk.. 18

साक्षात्कार

शमशेर सिंह मन्हास (जम्मू–काश्मीर भाजपा अध्यक्ष)................... 21

अन्य

भाजपा व्यापारी प्रकोष्ठ राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक....................... 23
मध्य प्रदेश : किसान बचाओ अनुष्ठान... 25
भाजपा गुजरात प्रदेश कार्यकारिणी बैठक..................................... 27
उपचुनाव में भाजपा की जीत.. 29

हमारे नवीनतम प्रकाशन

भारतीय जनता पार्टी, केन्द्रीय कार्यालय, 11 अशोक रोड, नई दिल्ली-110001, फोन- 011-23005796 के विक्रय केन्द्र पर उपलब्ध हैं

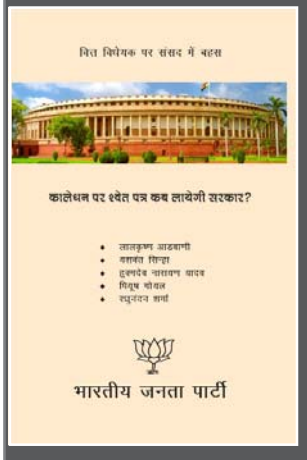

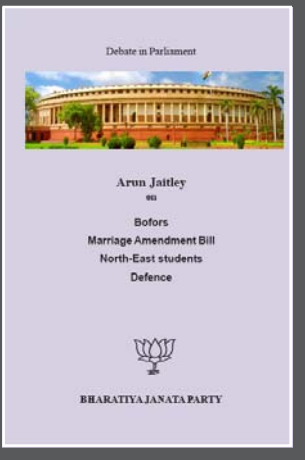

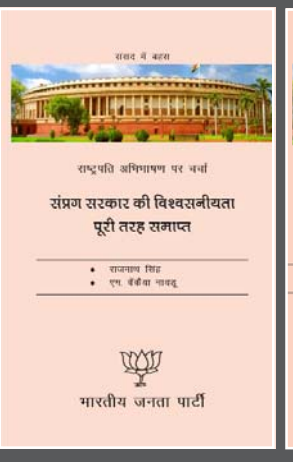

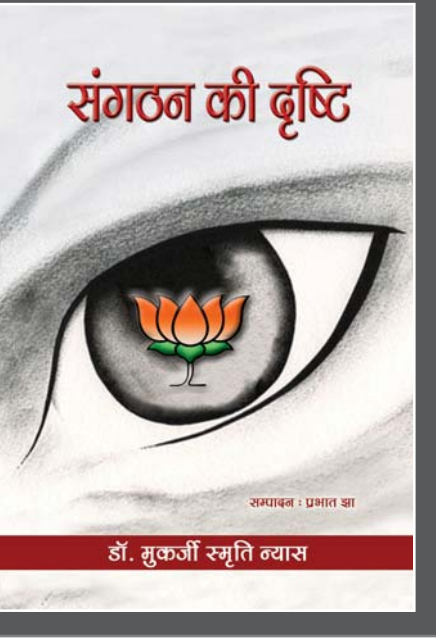

पाठक कृपया ध्यान दें!

fi; ikBdx.k]

राष्ट्रीय विचारों की प्रतिनिधि पाक्षिक पत्रिका 'कमल संदेश' (हिंदी/अंग्रेजी) की सदस्यता के लिए कृपया अपना नाम, पूरा पता (पिन कोड सहित), मोबाइल नं. के साथ अपना चैक/ड्राफ्ट ''डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास–कमल संदेश'' के नाम से नई दिल्ली में देय निम्न पते पर भेजें:

Mk- edth Lefr U;kl] पीपी–66, सुब्रह्मण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली– 110003,
फोनः 011–23381428, फैक्सः 011–23387887, ई–मेलः kamalsandesh@yahoo.co.in **&lEiknd**

महंगाई और भ्रष्टाचार के विरुद्ध निरंतर जनसंघर्ष जरूरी

समाधकीय

Hkkजपा कार्यकर्ताओं को फिर एक बार सड़कों पर उतरने को मजबूर होना पड़ा है। देशभर में लाखों लोगों ने भाजपा के 'जेल भरो आंदोलन' का खुलेआम समर्थन करते हुए केन्द्र में कांग्रेस–नीत–यूपीए सरकार की निर्मम असंवेदनशीलता का जबर्दस्त विरोध किया। हर तरफ एक ही आवाज यूपीए सरकार के खिलाफ गूंज रही थी– हमें गिरफ्तार करो! हमें जेल में डाल दो– यह था जेल भरो आंदोलन की पुकार! कांग्रेस–विरोधी, यूपीए विरोधी नारे आकाश को गुंजायमान कर रहे थे, लोग निराश होकर अपने आक्रोश और क्रोध को प्रगट कर रहे थे। पश्चिम में राजस्थान और गुजरात की गलियों से लेकर नागालैण्ड, असम और पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों तक लोगों ने कांग्रेस–नीत यूपीए सरकार की निष्ठुर और निर्मम असंवेदनशीलता के प्रति कड़ा आक्रोश जाहिर किया। दिल्ली, मध्यप्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखण्ड और कई राज्यों में जबर्दस्त विरोध प्रदर्शनों का आयोजन हुआ और इन सभी राज्यों में जेल भरो आंदोलन को लोगों का स्वतःस्फूर्त समर्थन मिला। अब तो यह स्पष्ट हो गया है कि लोग कांग्रेस–नीत यूपीए की नृशंसता, उसके भ्रष्टाचार और जन–क्रूरताओं को सहन नहीं कर सकते हैं। पूरा राष्ट्र कांग्रेस के राज्य में निरंतर बढ़ रही कीमतों और कमरतोड़ महंगाई की भर्त्सना करने के लिए खड़ा हो गया है।

कांग्रेस–नीत यूपीए सरकार ने फिर से पेट्रोल की कीमतों में 7.50 रुपए प्रति लीटर की भारी वृद्धि की है। यूपीए के दूसरे कार्यकाल के तीन वर्षों में इस प्रकार की बढ़ोतरी 11वीं बार देखने में आई है। आज उच्च मुद्रास्फीति दैनिक जीवन का अंग बन चुका है, खाद्य मुद्रास्फीति भी यूपीए के कार्यकाल के इन तीन वर्षों में दो अंकों तक रही है। यह समझ पाना मुश्किल हो गया है कि आखिर कांग्रेस–नीत यूपीए सरकार महंगाई के इस ज्वार भाटे में लोगों को राहत क्यों नहीं पहुंचा रही है? राहत की बजाय आम आदमी के लिए बढ़ती कीमतों से उसके दुःखों का कहीं अंत होता दिखाई नहीं पड़ता है। लोग मांगते हैं रोटी, मिलते हैं पत्थर! लगातार बढ़ती जा रही कीमतों से लोग– विशेष रूप से गरीब लोगों का जीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। यूपीए सरकार ने मई 2011 में एलपीजी के सिलेण्डरों पर भारी 50 रुपए और मिट्टी के तेल पर 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिए। सरकार ने जून 2010 में डीजल पर 2 रुपए प्रति लीटर और एलपीजी पर 35 रुपए प्रति सिलेण्डर बढ़ा दिया था और गरीब आदमी के खाने–पकाने के ईंधन केरोसिन पर भी 3 रुपए प्रति लीटर बढ़ाया था। यूपीए–II के शासन काल के अब कूकिंग गैस प्रति लीटर 85 रुपए महंगी हो गई हैं। कूकिंग फ्यूल की बढ़ोतरी से पहले ही घर के बजट पर इतना असर पड़ा है कि आम आदमी कुचल कर रह गया है और आवश्यक वस्तुओं में खाद्य पदार्थों के कीमतें आसमान पर पहुंच गई है। अब पेट्रोल की बढ़ी कीमतों से जिस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा, उससे तो उपभोक्ता जीते जी ही मर जाएगा।

यूपीए ने अर्थव्यवस्था को संभालने और प्रबंधन में बुरी तरह से गड़बड़ी की है। जीडीपी विकास दर में गिरावट से भी यूपीए सरकार की नीतियां और प्राथमिकताएं प्रभावित होती जा रही हैं। अभी हाल की बात है कि 'एस एंड पी' और 'फिच' जैसी अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने भी अर्थव्यवस्था की रेटिंग्स को डाउन ग्रेड करना शुरू कर दिया है। रुपया अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में गिरता जा रहा है क्योंकि कांग्रेस–नीत यूपीए सरकार नीतिगत अपंगता और मुद्रास्फीति का शिकार बनी हुई है। एक तरफ तो सरकार विदेशों में जमा काले धन के प्रति चुप्पी साध कर इसे वापस लाने में किसी प्रकार की प्रतिबद्धता नहीं दिखा रही है तो दूसरी तरफ हम आए दिन अखबारों की सुर्खियों में नए–नए

घपले, घोटाले और सरकारी धन के लूट की नई–नई कहानियां पढ़ने को मिल रही हैं। बजट में भी आम आदमी पर नए करों का बोझ डाला गया है, और उधर राजकोषीय घाटा बढ़ता जा रहा है और बढ़ती जा रही उधारी से तो निश्चित ही लोगों के लिए जीना दुश्वार हो जाएगा। पिछले कई वर्षों से लोग निरंतर बढ़ती जा रही कीमतों के बोझ तले दबे हुए हैं और उधर हम देख रहे हैं कि सरकार मूल्य–वृद्धि के मामले में बेहद असंवेदनशील बनी हुई है और इस सरकार के मंत्रीगण बड़ी निर्लज्जतापूर्वक तरह–तरह के स्पष्टीकरण देकर बढ़ती महंगाई का बचाव करने में जुटे हुए हैं।

भारतीय जनता पार्टी यूपीए सरकार की गलत आर्थिक नीतियों, व्यापक भ्रष्टाचार और भ्रमित प्राथमिकताओं से फैली मूल्य–वृद्धि के खिलाफ अथक संघर्ष करने में लगी हुई है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी ने 2010 में प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह से महंगाई पर 14 सवाल पूछे थे जिनका आज तक कोई जवाब नहीं मिल पाया है। 6 अप्रैल 2010 को श्री गडकरी ने फिर से महंगाई पर श्वेतपत्र की मांग की थी, परन्तु कोई लाभ नहीं हुआ। 21 अप्रैल 2010 को रामलीला मैदान में एक विराट महंगाई रैली का आयोजन किया गया, जिसमें देशभर से आए लाखों लोगों ने भाग लिया, परन्तु यूपीए सरकार ने बेलगाम बढ़ती महंगाई पर निष्क्रिय ही बनी रही। 21 जून 2010 को देशभर में भारत बंद का आयोजन हुआ। 15 दिसम्बर 2010 को यूपीए सरकार द्वारा पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में वृद्धि के खिलाफ राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शनों को आयोजन हुआ। पुनः 16 मई 2011 को भी पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में वृद्धि पर राष्ट्रव्यापी विरोध किया गया, जो यूपीए सरकार ने आठवीं बार मूल्य वृद्धि की थी। एक बार फिर राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया गया जब यूपीए सरकार ने एलपीजी की कीमतों में 50 रुपए प्रति सिलेण्डर और डीजल में 2 रुपए प्रति लीटर तथा मिट्टी के तेल में 2 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि 24 जून 2011 को की थी। भाजपा कार्यकर्ताओं ने पूरे देश में 4 नवम्बर 2011 को पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों की वृद्धि का विरोध किया। 31 मई 2012 को पूरे देश ने एनडीए के आह्वान पर भारत बंद का आयोजन किया, जो अत्यंत सफल रहा क्योंकि लोगों ने पूरे दिल से इस आह्वान पर सकारात्मक भागीदारी दिखाई।

7 जून 2012 से भाजपा ने जन संघर्ष अभियान की शुरूआत करते हुए इसका समापन 22 जून 2012 को जेल भरो आंदोलन से किया। लोगों को महंगाई के खिलाफ एकजुट करने के लिए भाजपा के प्रयासों को पूरे देश से भारी समर्थन प्राप्त हुआ और इस प्रकार भाजपा ने कांग्रेस–नीत–यूपीए के कुशासन और अराजकता के खिलाफ देश भर में लोगों की आवाज बुलंद की।

दुख की बात है कि महंगाई के प्रति लोगों की दुर्दशा को उजागर करने के लिए भाजपा ने जिस अथक प्रयास किया, उसके बावजूद भी कांग्रेस–नीत यूपीए सरकार टस से मस नहीं हुई। उसने लोगों को जरा भी राहत नहीं पहुंचाई और न ही उसने किसी प्रकार के ठोस उपाए किए। ऐसी परिस्थितियों में लोगों के पास एक मात्र यही विकल्प बचा रहता है कि वे संघर्ष और आंदोलन जारी रखें। भाजपा निरंतर लोगों की आवाज को बुलंद करने के लिए अथक संघर्ष करती चली आ रही है। भाजपा को जन–विरोधी कांग्रेस–नीत यूपीए के खिलाफ लोगों को एकजुट करना है। इसके परिणाम भी सभी के सामने हैं– कांग्रेस को हाल में हुए चुनावों में धूल चाटनी पड़ी है– ये चुनाव चाहे राज्य विधान सभाओं के हों या फिर संसद अथवा स्थानीय निकायों के हों। लोगों ने पक्का इरादा कर लिया है कि वे कांग्रेस को उसके छलपूर्ण व्यवहार और लोगों के साथ विश्वासघात पर सबक सिखाकर रहेंगे। प्रत्येक भाजपा कार्यकर्ता को लोगों का सिपाही बनना होगा, आम आदमी की आवाज बुलंद करनी होगी और लोगों को वोटों की लड़ाई तक ले जाना होगा ताकि देश को कांग्रेस–नीत यूपीए सरकार से मुक्ति मिल सके। प्रत्येक भाजपा कार्यकर्ता के लिए आवश्यक है कि वह लोगों की संगठित करे और संघर्ष में आगे ले जाए।

भाजपा ही देश की एकमात्र आशा है और उसे महंगाई तथा भ्रष्टाचार के खिलाफ लोगों की आवाज बुलंद कर उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना होगा।■

व्यंग्य चित्र

बेलगाम महंगाई के विरोध में जेल भरो आंदोलन को मिला देशव्यापी जन-समर्थन

कांग्रेस नीत यूपीए सरकार की जन–विरोधी नीतियों के कारण बेलगाम बढ़ती महंगाई एवं पेट्रोल के बढ़े दामों के खिलाफ 22 जून को भाजपा का "जेल भरो आन्दोलन" पूरे देश में पूर्णतः सफल रहा। इस 'जेल भरो आंदोलन' के दौरान देशभर के 528 जिलों में 15,000 स्थानों पर केंद्रीय नेता, प्रदेश के नेताओं तथा स्थानीय नेताओं के नेतृत्व में जून की चिलचिलाती धूप में 37 लाख से भी ज्यादा लोगों ने गिरफ्तारियां दीं।

गत 7 जून से प्रारंभ हुए 'जन–संघर्ष अभियान' के तहत पूरे देश में गांव–तहसील स्तर पर महंगाई व पेट्रोल के बढ़े दामों के खिलाफ पदयात्राओं, रैलियों, सभाओं और धरनों के माध्यम से केन्द्र सरकार की जनविरोधी नीतियों को उजागर किया गया। इस "जन जागरण अभियान" में विभिन्न प्रदेशों में 16,036 (सोलह हजार छतीस) पदयात्राओं, सभाओं एवं रैलियों के कार्यक्रम हो चुके हैं जिसमें लाखों की संख्या में लोगों ने भागीदारी की।

देश के विभिन्न भागों में आयोजित जेल भरो आन्दोलन कार्यक्रम में प्रमुख रूप से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गड़करी ने नागपुर में, श्री अरुण जेटली, श्री राजनाथ सिंह, श्री रामलाल जी, श्री मुख्तार अब्बास नकवी, श्री तरुण विजय एवं डा0 हर्ष वर्धन ने दिल्ली में, श्री एम. वैंकेया नायडू ने हैदराबाद में, श्रीमती सुषमा स्वराज ने भोपाल, श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने मुरैना (मध्यप्रदेश) में, श्रीमती स्मृति ईरानी ने जम्मू में, श्रीमती वसुन्धरा राजे सिन्धिया ने झालावाड़, श्री किरीट सोमैया ने जयपुर में एवं श्रीमती किरन माहेश्वरी ने चित्तौड़गढ़ (राजस्थान) में, श्री अनन्त कुमार बंगलुरु में, श्री रविशंकर प्रसाद एवं श्रीमती किरण घई पटना में, श्री जे0पी0 नड्डा चण्डीगढ़ में, श्री धर्मेन्द्र प्रधान रायपुर (छत्तीसगढ़) में, श्री पुरुषोत्तम रुपाला ने गुजरात में, श्री कलराज मिश्रा, श्री अनुराग ठाकुर ने शिमला (हिमाचल प्रदेश) में, उत्तरांचल में श्री भगतसिंह कोश्यारी उधमसिंह नगर में, श्री थावरचन्द गहलोत ने देहरादून में, श्री प्रकाश जावडेकर ने पणजी (गोवा) में, श्री बलवीर पुंज ने पंजाब में, श्री चन्दन मित्रा और श्रीमती विजया चक्रवर्ती ने गुवाहाटी में, श्रीमती नजमा हेपतुल्ला ने दादर नागर हवेली में, श्री मुरलीधर राव ने हैदराबाद में, श्रीमती आरती मेहरा ने केरल में, डा0 के लक्ष्मण ने चैन्नई में, सुश्री वाणी त्रिपाठी ने पुडुचेरी में, श्री श्याम जाजू ने फरीदाबाद में, श्री ओमप्रकाश धनकड़ ने झज्जर में, श्री रामनाथ कोविंद ने अगरतल्ला (त्रिपुरा) में और तापिर गांव ने ईंटानगर में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ गिरफ्तारियां दीं।

महाराष्ट्र

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी ने बेलगाम महंगाई और भ्रष्टाचार के विरोध में राष्ट्रव्यापी जेल भरो आंदोलन के दौरान नागपुर में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ गिरफ्तारी दी। शहर में गांधी प्रतिमा के पास कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्री गडकरी ने बढ़ती कीमतों और देश में व्याप्त भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने में संप्रग सरकार की विफलता के लिए आलोचना की। उन्होंने कहा कि केंद्र की यह जनविरोधी सरकार सभी मोर्चों पर विफल रही है। बेलगाम महंगाई के चलते आम आदमी को दो वक्त का भोजन जुटाने में पसीना छूट रहा है। इस आंदोलन में राज्यसभा सांसद अजय कुमार संचेती, पूर्व सांसद बनवारी लाल पुरोहित, पार्टी विधायक कृष्णा खोपडे, विकास कुंभरे, सुधीर पर्वे, नाना पटोले सहित अनेक पार्टी नेताओं ने गिरफ्तारी दीं। विदर्भ के विभिन्न भागों में आवश्यक वस्तुओं और पेट्रोल मूल्य वृद्धि के विरोध में भाजपा के हजारों नेताओं और कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारी दीं।

दिल्ली

तपती धूप की परवाह किए बगैर भाजपा के 30 हजार से अधिक कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष श्री विजेन्द्र गुप्ता के नेतृत्व में जंतर मंतर पर अभूतपूर्व सत्याग्रह करके सरकार

को यह बता दिया कि जनता उससे त्राहिमाम कर चुकी है। इस सरकार के दिन लद चुके हैं। प्रधानमंत्री निवास की ओर 7 प्रमुख चौराहों से कूच कर रहे 20 हज़ार पुरूष कार्यकर्ताओं और 6 हजार महिला कार्यकर्ताओं को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया और जेल में जगह न होने के कारण गिरफ्तारी स्थल को ही जेल घोषित कर सबको पुलिस निगरानी में रखा। पुलिस हिरासत में कार्यकर्ता नारे लगा रहे थे – 'खून चूसने वाली कांग्रेस सरकार को – बर्खास्त करो, बर्खास्त करो', 'भ्रष्टाचारी मंहगाई बढ़ाने वाली दिल्ली सरकार – निकम्मी है निकम्मी है', 'जो सरकार निकम्मी है – वो सरकार बदलनी है'। आक्रोशित कार्यकर्ता दिल्ली में पानी–बिजली की भीषण किल्लत के लिए शीला सरकार को जिम्मेदार बताते हुए पानी की किल्लत तुरन्त दूर करने की मांग सरकार से कर रहे थे। जनसभा में मंच संचालन श्री रमेश बिधूड़ी ने किया।

जनसभा के बाद सभी नेतागण प्रधानमंत्री की ओर बढ़े। पुलिस ने सर्वप्रथम राज्यसभा में विपक्ष के नेता श्री अरूण जेतली, भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुख्तार अब्बास नकवी, प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा, विजेन्द्र गुप्ता और रामेश्वर चौरसिया को गिरफ्तार किया। इसके बाद हजारों की तादाद में नारे लगाते हुए पुरूष और महिला कार्यकर्ता आगे बढ़े। उनमें जेल भरने का इतना जुनून था कि पुलिस के पसीने छूट गए। 26 हज़ार लोगों को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने हाथ जोड़ दिए और गिरफ्तारी देने को तैयार कार्यकर्ताओं को बंदी बनाने से साफ इंकार कर दिया।

दिल्लीभर से आक्रोशित कार्यकर्ता सुबह 10 बजे से ही जंतर मंतर पर जुटने लगे थे। जैसे–जैसे सूरज तपा कार्यकर्ताओं का हुजूम विशाल समागम में बदल गया। गुस्से से भरे कार्यकर्ताओं ने सरकार विरोधी गगनभेदी नारे लगाए और मुख्यमंत्री की बर्खास्तगी की मांग की।

मध्य प्रदेश

महंगाई को लेकर भाजपा द्वारा आयोजित जेल भरो आंदोलन के तहत पूरे प्रदेश के जिला मुख्यालयों पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन और सभा कर गिरफ्तारियां दी। पार्टी नेताओं ने महंगाई के मसले के साथ साथ प्रदेश के साथ किये जा रहे भेदभाव पर भी केन्द्र को जमकर कोसा। राजधानी में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष श्रीमती सुषमा स्वराज यूपीए सरकार पर खूब बरसीं। उन्होंने महंगाई की वजह केन्द्र के मंत्रियों के भ्रष्टाचार को करार दिया। केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों के साथ किये जा रहे भेदभाव को भी उन्होंने बड़ा मुद्दा बताया। प्रदेश भाजपा कार्यालय दीनदयाल परिसर में जेल भरो आंदोलन के तहत आयोजित सभा को संबोधित करते हुए श्रीमती स्वराज ने कहा कि यूपीए सरकार को राज करते हुए आठ साल हो गये हैं। आम आदमी को राहत देने के नाम पर आई यह सरकार आम आदमी को असहनीय कष्ट दे रही है।

दीनदयाल परिसर के बाहर सभास्थल पर ही मंच से जिला प्रशासन के अफसरों ने मौजूद कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी और रिहाई की घोषणा कर दी। श्रीमती सुषमा

स्वराज का भाषण समाप्त होते ही एडीशनल कलेक्टर मंच पर आये और कहा कि इस परिसर को खुली जेल मानकर यहां मौजूद सात हजार सात सौ कार्यकर्ता गिरफ्तार और रिहा किये जाते हैं।

राजस्थान

बढ़ती मंहगाई और पेट्रोल की बढ़ी दरें वापस लेने की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी के देशव्यापी 'जेल भरो आन्दोलन' के तहत राजस्थान में भाजपा के हजारों कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर गिरफ्तारियां दीं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अरूण चतुर्वेदी, राष्ट्रीय नेता श्री किरीट सौमैय्या, पूर्व सांसद श्री रामदास अग्रवाल समेत सैकेड़ों कार्यकर्ताओं ने जयपुर में और नेता प्रतिपक्ष श्रीमती वसुंधरा राजे के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने झालावाड में गिरफ्तारियां दीं। डॉक्टर चतुर्वेदी ने जयपुर में गिरफ्तारी देने से पहले कार्यकर्ताओं को

सम्बोधित करते हुए कहा कि केन्द्र सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के कारण आम लोगों का जीना दूभर हो गया है। पेट्रोल, डीजल की दरों में जितनी बढ़ोतरी तीन साल में हुई है, इससे पहले कभी नहीं हुई। उन्होंने कहा कि मंहगाई लगातार बढती जा रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही है, देशवासी बढ़ती मंहगाई और भ्रष्ट्राचार से परेशान हैं। राष्ट्रीय नेता किरीट सौम्मैया, पूर्व सांसद रामदास अग्रवाल, पूर्व मंत्री और विधायक घनश्याम तिवाड़ी ने भी कार्यकर्ताओं को सम्बोधित किया। नेता प्रतिपक्ष वसुंधरा राजे ने झालावाड में गिरफ्तारी देने से पहले केन्द्र और राज्य सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि मंहगाई, भ्रष्टाचार से आम नागरिक दुखी है। पेट्रोल और डीजल के बढ़ी दरों से आम नागरिक और किसान परेशान है। उन्होंने इस मौके पर 'जय–जय राजस्थान' का नारा भी दिया। जयपुर, झालावाड के अलावा, बूंदी, कोटा, उदयपुर, अजमेर, जैसलमेर समेत प्रदेश भर से भाजपा कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारियां दीं।

बिहार

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डा. सीपी ठाकुर, राष्ट्रीय महामंत्री एवं सांसद श्री रविशंकर प्रसाद एवं भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रो. किरण घई के नेतृत्व में पार्टी कार्यालय से राजभवन मार्च निकला। इस दौरान सैकड़ों नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने यूपीए सरकार के विरोध में नारे लिखे तख्तियां थाम रखी थीं। जुलूस में केन्द्र सरकार के विरोध में नारेबाजी हुई। राजभवन मार्च में प्रदेश भाजपा के तमाम मंचों के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने सैंकड़ों की संख्या में हिस्सा लिया। डा. सीपी ठाकुर एवं श्री रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने राजभवन में जाकर राज्यपाल श्री देवानंद कुंवर को चार सूत्री मांगों को ज्ञापन सौंपा। प्रदेश भाजपा की ओर से बिहार को 1820 मेगावाट की जगह 3000 मेगावाट बिजली उपलब्ध कराने और कोल लिंकेज एवं विशेष राज्य का दर्जा देने, महंगाई पर अविलंब रोक लगाने तथा भ्रष्टाचार में संलिप्त मंत्रियों एवं नेताओं पर कार्रवाई करने की मांग केन्द्र सरकार से की गई है। मार्च में भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रो. किरण घई, सांसद श्री रमा देवी, प्रदेश महामंत्री श्री मंगल पाण्डेय, विधायक सर्वश्री अरुण कुमार सिन्हा, अनिल कुमार, सत्येन्द्र कुशवाहा, लालबाबू प्रसाद, सुधीर शर्मा, पीके सुधांशु, संजीव क्षत्रिय और दिलीप कुमार सिंह समेत अन्य नेता शामिल हुए।

झारखंड

भाजपा झारखंड प्रदेश अध्यक्ष डॉ. दिनेशानंद गोस्वामी के नेतृत्व में चास–बोकारो के कार्यकर्ता जेल भरो आंदोलन में शामिल हुए। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए डॉ. गोस्वामी ने कहा कि केन्द्र की कांग्रेस नीत यूपीए सरकार भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी है। देश में महंगाई चरम पर है, आठ वर्ष में यूपीए सरकार ने लोगों का जीवन कठिन बना दिया है। इसके विरोध में भाजपा सड़क से संसद तक आंदोलन करेगी। डॉ.गोस्वामी ने कहा कि केन्द्र सरकार झारखंड के साथ लगातार भेदभाव कर रही है। राज्य में 1800 किमी राष्ट्रीय राजमार्ग की जवाबदेही केन्द्र सरकार पर है। लोक उपक्रम मुनाफा कमा रहे हैं लेकिन वे रोजगार व शिक्षा के क्षेत्र में निवेश नहीं कर रहे हैं। बीएसएल व बीसीसीएल ने नौजवानों के लिए इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक कालेज नहीं खोला है। कहा कि झारखंड के कोयले से दिल्ली व मुम्बई जगमगाता है। हमारे यहां पावर यूनिट के लिए कोयला नहीं है। कोयले की रायल्टी मूल्य के आधार पर नहीं दी जाती है। डॉ. गोस्वामी ने कहा कि डीवीसी व कोल इंडिया का मुख्यालय राज्य के बाहर है। इससे राज्य सरकार को नुकसान हो रहा है। केन्द्र से सीधी राशि पंचायत के लिए

नहीं दी जा रही है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्य प्रभावित हो रहा है। केन्द्र सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हो रही है।

उत्तराखंड

भ्रष्टाचार और महंगाई के खिलाफ भाजपा के कार्यकर्ताओं ने राजधानी दून समेत सभी जिला मुख्यालयों पर जोरदार प्रदर्शन किया और गिरफ्तारी दी। भाजपा नेताओं ने केंद्र की नीतियों और प्रदेश की कांग्रेस सरकार की कार्यशैली पर भी जमकर निशाना साधा। भ्रष्टाचार व महंगाई के खिलाफ गढ़वाल व कुमाऊं मंडल में हजारों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। राजधानी दून में प्रदेश प्रभारी थावर चंद्र गहलोत, पूर्व सीएम श्री भुवनचंद्र खंडूड़ी व पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हरबंस कपूर तथा हरिद्वार में पूर्व सीएम श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' के नेतृत्व में भाजपाइयों ने प्रदर्शन कर गिरफ्तारियां दीं। टिहरी उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, कोटद्वार में भी गिरफ्तारियां दी गई। कुमाऊं मंडल के हल्द्वानी(नैनीताल) में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री बिशन सिंह चुफाल, नैनीताल में श्री बची सिंह रावत, रुद्रपुर(उधमसिंहनगर) में पूर्व सीएम श्री भगत सिंह कोश्यारी के नेतृत्व में गिरफ्तारी दी गईं।

हिमाचल प्रदेश

लगातार बढ़ती मंहगाई के खिलाफ हिमाचल प्रदेश भाजपा के नेताओं ने प्रदेशभर में धरने प्रदर्शन तथा रैलियों का आयोजन कर गिरफ्तारियां दी। पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर आयोजित जेल भरो आंदोलन के तहत शिमला में पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं हिमाचल भाजपा के प्रभारी कलराज मिश्र एवं भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सांसद अनुराग ठाकुर के नेतृत्व में सैंकड़ों पार्टी कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारियां दी। गिरफ्तारी देने से पूर्व भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं प्रदेश प्रभारी कलराज मिश्र ने कहा कि आज कांग्रेसनीत यूपीए सरकार भ्रष्टाचार एवं घोटालों की पर्याय बन गयी हैं। महंगाई दिन प्रतिदिन आसमान छू रही हैं। लेकिन केन्द्र सरकार का महंगाई रोकने में कोई नियंत्रण नहीं हैं। जिसके फलस्वरूप आवश्यक वस्तुओं की कीमतें आम आदमी की पहुंच से बाहर हो रही हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुराग ठाकुर ने अपने सम्बोधन में कहा कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अर्थशास्त्री होने के बावजूद भी देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में पूरी तरह असफल साबित हुए हैं।

चंडीगढ़

पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि के विरोध में भारतीय जनता पार्टी के हजारों नेताओं और कार्यकर्ताओं ने देशव्यापी जेल भरो आंदोलन के तहत चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा व देश के विभिन्न हिस्सों में गिरफ्तारियां दीं। पेट्रोल के बढ़े दामों, महंगाई एवं भ्रष्टाचार के खिलाफ अपना रोष दर्ज कराने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, सांसद एवं प्रवक्ता जगत प्रकाश नड्डा के नेतृत्व में चंडीगढ़ प्रदेश अध्यक्ष संजय टंडन, पूर्व केंद्रीय मंत्री हरमोहन धवन एवं पूर्व सांसद सत्यपाल जैन सहित 953 कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारियां दीं।

पंजाब

भाजपा के पंजाब प्रदेश प्रभारी शांता कुमार व विधायक मनोरंजन कालिया ने जालंधर, भाजपा के राष्ट्रीय नेता बलवीर पुंज ने सांसद नवजोत सिंह सिद्धू, युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राजेश हनी और हजारों कार्यकर्ताओं सहित

अमृतसर में जबकि प्रदेश अध्यक्ष व विधायक अश्विनी शर्मा ने 5000 से अधिक कार्यकर्ताओं सहित पठानकोट में गिरफ्तारी दी। जालंधर में शांता कुमार ने कहा कि केंद्र सरकार दावा कर रही है कि कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि के कारण उसे मजबूरन पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि करनी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि भारत अकेला कच्चा तेल मंगाने वाला देश नहीं है बल्कि पूरे विश्व के देश कच्चे तेल का प्रयोग करते हैं। इसके बावजूद पाकिस्तान में पेट्रोल कीमतें सिर्फ 59 रुपये प्रति लीटर हैं, जबकि श्रीलंका में 61 रुपये

70 पैसे, बांग्लादेश में 43 रुपये 40 पैसे, यूएसए में 53 रुपये 70 पैसे और रूस में 50 रुपये 20 पैसे के हिसाब से पेट्रोल बिक रहा है। इससे साफ है कि इन कीमतों के पीछे अंतरराष्ट्रीय मंडी के उतार–चढ़ाव जिम्मेदार नहीं हैं बल्कि केंद्र सरकार की बदनीयत है। अमृतसर में बलवीर पुंज ने कहा कि केंद्र पेट्रोल की कीमतों के बाद अब रसोई गैस, मिट्टी के तेल और डीजल की कीमतों में भी इजाफा करने की तैयारी कर रही है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार को रेवेन्यू न्यूट्रल पालिसी अपनानी चाहिए जिसके तहत बढ़ी कीमतों पर लगने वाले टैक्सों में कटौती करके ग्राहकों को इसका लाभ देना चाहिए। उक्त के अलावा प्रदेश महासचिव कमल शर्मा ने लुधियाना में, महिला मोर्चो की प्रदेश अध्यक्ष रेणू थापर व महासचिव मनजीत सिंह राय ने बठिंडा में, राज्यसभा सदस्य अविनाश राय खन्ना ने संगरूर और बलराम जी दास टंडन ने पटियाला में गिरफ्तारियां दी। होशियारपुर में पूर्व मंत्री तीक्ष्ण सूद, फिरोजपुर में पूर्व प्रदेशाध्यक्ष ब्रिज लाल रिणवा, गुरदासपुर में पूर्व मंत्री अरुणेश शाकर, कपूरथला में पूर्व मंत्री मास्टर मोहन लाल, फाजिल्का में बलदेव राज चावला, बरनाला में हरजीत सिंह ग्रेवाल, नवांशहर में विजय सांपला ने, मानसा में पूर्व सांसद बीबी गुरचरण कौर, वरिंदर कौर ठांडी ने मोहाली और प्रदेश सचिव संदीप रिणवा ने मोगा में स्थानीय पार्टी पदाधिकारियों व सैंकड़ों कार्यकर्ताओं समेत गिरफ्तारी दी।

हरियाणा

भाजपा के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष कृष्णपाल गुर्जर और राष्ट्रीय सचिव श्याम जाजू के नेतृत्व में फरीदाबाद, राष्ट्रीय सचिव कैप्टन अभिमन्यु और प्रदेश उपाध्यक्ष मनीष ग्रोवर के नेतृत्व में रोहतक और किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओमप्रकाश धनखड़ के नेतृत्व में झज्जर में गिरफ्तारी दी गई। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष कृष्णपाल गुर्जर ने यहां बताया कि महेंद्रगढ़ में पूर्व मंत्री रामबिलास शर्मा व हजकां नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री चंद्रमोहन के नेतृत्व में गिरफ्तारी दी गई। पानीपत में पूर्व केंद्रीय मंत्री आइडी स्वामी व पूर्व विधायक हरि सिंह नलवा, हिसार में भाजपा के प्रदेश महामंत्री वीर कुमार यादव और हजकां नेता निहाल सिंह मताना, सिरसा में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रो. गणेशी लाल व हजकां नेता वीरभान मेहता के नेतृत्व में, भिवानी में विधायक घनश्याम सर्राफ व हजकां के प्रदेश महामंत्री वीरेंद्र कुमार के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारी दी। गुड़गांव में पूर्व सांसद सुधा यादव तथा पूर्व मंत्री राव नरबीर, सोनीपत में प्रदेश मीडिया प्रभारी राजीव जैन, विधायक कविता जैन, अंबाला में पूर्व सांसद रतन लाल कटारिया, जींद में पूर्व सांसद किशन सिंह सांगवान और पलवल में पूर्व सांसद रामचंद्र बैंदा व प्रदेश महामंत्री दीपक मंगला के नेतृत्व में गिरफ्तारी दी गई। प्रदेश अध्यक्ष कृष्णपाल गुर्जर ने बताया कि यमुनानगर में प्रदेश महामंत्री घनश्याम दास, कुरुक्षेत्र में पूर्व विधायक कंवरपाल, कैथल में आत्मप्रकाश मनचंदा व धर्मवीर डागर, फतेहाबाद में प्रदेश उपाध्यक्ष जगदीश चोपड़ा और सुभाष बराला, रेवाड़ी

में प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष यादव, मेवात में गोवंश प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक भानी राम मंगला, करनाल में पूर्व उद्योग मंत्री शशिपाल मेहता, पंचकूला में प्रदेश उपाध्यक्ष रोजी मलिक व कोषाध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता के नेतृत्व में गिरफ्तारियां दी गई।

पश्चिम बंगाल

महंगाई व भ्रष्टाचार के खिलाफ जेल भरो आन्दोलन के तहत भाजपा कार्यकर्ताओं ने हावड़ा के जिलाधिकारी के कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। जुलूस निकाला। जुलूस के आगे बढ़ने पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया, जिसमें कुछ प्रदर्शनकारियों को चोट आई। पुलिस ने 214 भाजपा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया। सुबह 11 बजे से भाजपा कार्यकर्ता जिला मुख्यालय में जुटने लगे थे। पुलिस भी पहले से तैयार थी पुलिस ने एहतियात के तौर पर डीएम बंगले के मुख्य द्वार के सामने बैरिकेड कर रखा था, जिसे प्रदर्शनकारियों ने तोड़कर डीएम बंगले में घुसने का प्रयास किया। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाही करते हुए 214 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। बाद में सभी को हावड़ा थाने में लाने के बाद रिहा कर दिया गया। जेल भरो आंदोलन की अगुवाई शंभु शर्मा ने की। इस दौरान प्रदेश भाजपा के कार्यकारी सदस्य कामेश्वर तिवारी, महासचिव (हावड़ा) दिलीप गांगुली, उपाध्यक्ष अनिता हेरावत, उत्तर हावड़ा के महासचिव विनय अग्रवाल मौजूद रहे।

जम्मू-कश्मीर

संप्रग सरकार की नीतियां, महंगाई व भ्रष्टाचार के खिलाफ सड़क पर उतरे सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रव्यापी जेल भरो आंदोलन के तहत गिरफ्तारी दी। जम्मू में प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व सांसद व भाजपा राष्ट्रीय महिला मोर्चा अध्यक्ष स्मृति ईरानी ने किया। राज्य के 12 जिलों में प्रदर्शन हुए। सुबह साढ़े ग्यारह बजे डोगरा चौक पर प्रदर्शन के बीच स्मृति ईरानी ने दो सौ कार्यकर्ताओं के साथ बसों में चढ़कर गिरफ्तारी दीं। इससे पूर्व स्मृति ने कहा कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भ्रष्टाचार व महंगाई के मुद्दे पर आंखें मूंद लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। कठपुतली की तरह काम करने वाले अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री ने लोगों से किया वादा पूरा नहीं किया। दूसरी ओर राज्य में ट्विटर मुख्यमंत्री अब्दुल्ला को अवाम की कोई फिक्र नहीं है। वह लोगों से विमुख होकर ट्विटर पर सक्रिय हैं। उमर ट्वीट पर घोटालों के बारे में एक शब्द नहीं लिखते हैं। भाजपा नेता ने कहा कि देशवासी कांग्रेस व उसकी समर्थक पार्टियों से विमुख हो गए देशवासी उन्हें सबक सिखाएंगे। प्रदेश भाजपा के सह प्रभारी आरपी सिंह, प्रदेश अध्यक्ष शमशेर सिंह मन्हास, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य अशोक खजुरिया, डॉ. जितेंद्र सिंह समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। प्रदेश अध्यक्ष शमशेर सिंह मन्हास ने कहा कि कुप्रशासन की शिकार जनता स्थानीय निकाय चुनाव में कांग्रेस, नेकां को असलियत दिखा देगी।

गुजरात

अहमदाबाद में मूल्य वृद्धि के खिलाफ 'जेल भरो आंदोलन' के दौरान हजारों कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारी दी। 231 स्थानों पर विरोध–प्रदर्शन आयोजित किया गया।

प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री आर. सी. फालदू ने कहा कि यूपीए सरकार कीमतों को नियंत्रित करने में विफल रही है। हजारों कार्यकर्ताओं के साथ श्री फालदू ने सूरत में प्रदर्शन किया जहां उन्होंने गिरफ्तारी दी। भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री पुरुषोत्तम रूपाला एवं सांसद श्री हरिन पाठक ने भी गिरफ्तारी दी। सौराष्ट्र भर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पार्टी के राष्ट्रव्यापी जेल भरो आंदोलन के तहत गिरफ्तारियां दीं। विभिन्न शहरों और कस्बों में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नीत संप्रग सरकार की गलत नीतियों से आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों के खिलाफ नारे लगाए। अकेले, राजकोट शहर में

2,581 भाजपा कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए।

कर्नाटक

कर्नाटक में भी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष केएस ईश्वरप्पा, राष्ट्रीय महासचिव एचएन अनंत कुमार सहित 100 से अधिक कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारियां दीं।

तमिलनाडू

चेन्नई में भाजपा के हजारों कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारियां दीं। तमिलनाडु में 3600 से अधिक पार्टी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया।

असम

असम के गुवाहाटी में भाजपा के लगभग 20 हजार कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारियां दीं। सांसद चंदन मित्रा, विजय चक्रवर्ती और रमन डेका ने राज्य में विभिन्न स्थानों पर विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया। डॉ. मित्रा ने गुवाहाटी में गिरफ्तारी दी। ■

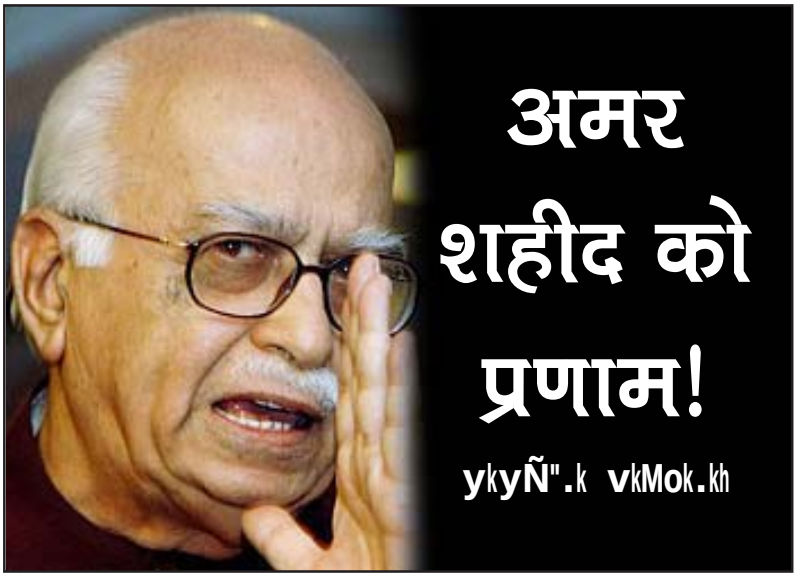

vkज 23 जून है। यह वह दिवस है, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। ठीक 59 वर्ष पूर्व, 1953 में इसी दिन डॉ. श्यामा प्रसाद मुकर्जी का स्वर्गवास रहस्मय परिस्थितियों में श्रीनगर में हो गया था।

अक्टूबर 1951 में, डॉ. मुकर्जी ने भारतीय जनसंघ की स्थापना की। वह इसके प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित हुए। 1952 में, निर्वाचन आयोग ने लोकसभा और विधान सभाओं के प्रथम आम चुनाव कराए। डॉ. मुकर्जी कलकत्ता के एक निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुए।

दिसम्बर 1952 में जनसंघ का प्रथम अधिवेशन कानपुर में हुआ। इसी अधिवेशन में डॉ. मुकर्जी ने देश का आह्वान करते हुए जम्मू और काश्मीर राज्य को भारत संघ से पूर्णतः विलय करने का आग्रह किया। इस आह्वान को अत्यंत शक्तिशाली नारे में समाहित किया गया था:

एक देश में,
दो विधान, दो प्रधान, दो निशान
नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे

कानपुर सत्र का समापन इस संकल्प से किया गया कि जम्मू और काश्मीर राज्य का संघ के साथ पूर्ण विलय के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जाए।

अभियान से पूर्व डॉ. मुकर्जी का प्रधानमंत्री पं. नेहरू के साथ जम्मू और काश्मीर के पूर्ण विलय के विषय पर पत्राचार हुआ था।

इसके बाद डॉ. श्यामा प्रसाद मुकर्जी ने इस मुद्दे पर पूरे देश का दौरा किया। अपने इस दौरे में उनके साथ श्री अटल बिहारी वाजपेयी भी साथ रहे थे।

मैं उन दिनों कोटा, राजस्थान में था।

मैं कोटा रेलवे स्टेशन पर इन दो महान विभूतियों से मिलना कभी भूल नहीं सकता, जबकि वे कोटा जंकशन से गुजर रहे थे।

जम्मू और काश्मीर का आदेश था कि कोई भी राज्य में आने वाला व्यक्ति केवल राज्य सरकार से परमिट प्राप्त करके ही राज्य में दाखिल हो सकेगा। डॉ. मुकर्जी ने राज्य सरकार के इस आदेश को भारत के संविधान का उल्लंघन माना। अतः उन्होंने निर्णय किया कि वह स्वयं ही कथित आह्वान के मोर्चे पर अभियान की अगुआई करते हुए

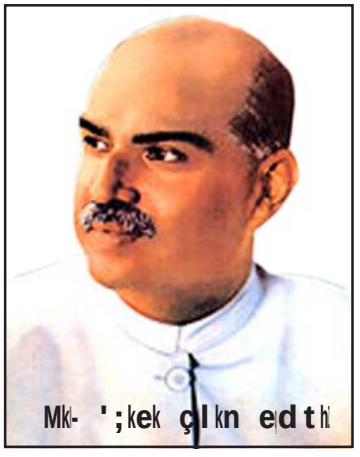

प्रवेश पत्र (एंट्री–परमिट) आदेश को तोड़ेंगे।

डॉ. मुकर्जी 8 मई 1953 को काश्मीर गंतव्य स्थल के लिए दिल्ली से एक पैसेंजर ट्रेन में रवाना हो गए और उनके साथ अनेक अनुयायी पंजाब में प्रवेश कर गए। पूरे पंजाब में देखने को मिला कि लोगों की अपार भीड़ हर स्थान पर जुटी हुई थी।

उनका अंतिम स्टॉप पंजाब की पांच महान नदियों में से एक नदी रावी पर बनी सीमा चैक–पोस्ट था, जहां से पंजाब और जम्मू तथा काश्मीर के बीच सीमा स्थापित होती है। राज्य में उनका प्रवेश 10 मई 1953 को हुआ। रावी पर एक सड़क–पुल था। माना जाता था कि इन दो राज्यों के बीच सीमा इस माधोपुर पुल के मध्य–बिन्दु पर स्थित थी। जब डॉ. मुकर्जी की जीप उन्हें लेकर पुल के मध्य–बिन्दु पर पहुंची तो देखा गया कि जम्मू और काश्मीर पुलिस का एक दल सड़क को रोक कर खड़ा था। कठुआ (जम्मू और काश्मीर राज्य) के पुलिस अधीक्षक ने राज्य के चीफ सेक्रेटरी (मुख्य सचिव) का हस्ताक्षर किया हुआ एक आदेश सौंपा जिसमें राज्य में डॉ. मुकर्जी के घुसने पर प्रतिबंध लगाया गया था। परन्तु डॉ. मुकर्जी ने कहा कि "मैं तो राज्य में प्रवेश करने के लिए कटिबद्ध हूं।"

शेष पृष्ठ 20 पर

अमर शहीद डॉ. मुकर्जी की मां श्रीमती जोगमाया देबी द्वारा तत्कालीन प्रधानमंत्री पं. नेहरु को लिखे गये पत्र का पूरा पाठ

77, आशुतोष मुकर्जी रोड, कोलकाता
4 जुलाई, 1953

प्रिय नेहरु,

आपका 30 जून को लिखा हुआ पत्र मुझे 2 जुलाई को बिधान चन्द्र रॉय द्वारा मिला! आपके संदेश और सहानुभूति के लिए धन्यवाद!

सारा राष्ट्र अपने प्रिय पुत्र के गुजर जाने का दुःख मना रहा है! माँ होने के नाते मेरा दुःख इतना गहरा और गंभीर है कि मैं व्यक्त करने में अक्षम हूँ! मैं यह पत्र आपसे किसी सहानुभूति की अपेक्षा में नहीं लिख रही हूँ बल्कि आपसे न्याय की माँग कर रही हूँ! मेरे बेटे की कैद में मृत्यु हुयी है––कैद में––बिना किसी सुनवाई के! आपने अपने पत्र में इस बात पर जोर दिया कि कश्मीर सरकार ने वह सब किया जो भी किया जाना चाहिए था! आपके आश्वासन का आधार संभवतः आपको दिए गए आश्वासनों और सूचना पर आधारित था! मैं पूछती हूँ कि ऐसे व्यक्तियों के द्वारा दी गयी सूचना का क्या मूल्य, जिन्हें कि आज खुद कटघरे में खड़ा होना चाहिए था! आप कहते हैं कि जिन दिनों मेरा पुत्र बंधक था उन दिनों आपने कश्मीर का दौरा किया था! आपके अनुसार आपको मेरे पुत्र से अत्यंत स्नेह था! मुझे आश्चर्य होता है कि तब आपको मेरे बेटे का स्वयं हाल पता करने और उसके स्वास्थ्य तथा अन्य प्रबंधों के बारे में जानकारी प्राप्त करने से किस बात ने रोका था?

उसकी मौत रहस्य में घिरी है ! सबसे अधिक आश्चर्य में डालने वाली और सदमा पहुंचाने वाली बात यह है कि मेरे बेटे कि मृत्यु के बाद पहली खबर, जो जम्मू और कश्मीर की राज्य सरकार ने मुझे दी, वह उसकी मृत्यु के मात्र दो घंटे बाद ही तार द्वारा मुझ तक पहुंची! और तार कितने क्रूरतापूर्ण ढंग से दिया गया! मेरे बेटे की मृत्यु की खबर मुझे पहले मिली और मेरे बेटे द्वारा भेजा गया तार कि उसकी खराब तबीयत के कारण उसे अस्पताल ले जाया जा रहा है यह बाद में!

मुझे निश्चित सूचना मिली है कि मेरे बेटे की तबीयत शुरू से ही, बंधक बनाये जाने के बाद से ही नहीं ठीक चल रही थी! उसकी तबीयत गंभीर रूप से कई बार खराब हो चुकी थी! मैं पूछती हूँ कि तब कश्मीर सरकार ने या आपने स्वयं मुझे और उसके परिवार को इस बात की सूचना क्यों नहीं दी?

और जब मेरे बेटे को अस्पताल भेजा गया तब भी कश्मीर सरकार ने मुझे या बिधान चन्द्र रॉय को इस बात की सूचना देना जरूरी नहीं समझा! यह भी साफ जाहिर है की कश्मीर सरकार ने मेरे बेटे के पूर्व चिकित्सा विवरण भी जानने की कोशिश नहीं की ताकि वक्त पड़ने पर सही देखभाल के इंतजाम कराये जा सकें! मेरे बेटे की बार बार तबीयत खराब होने पर भी कोई चेतावनी नहीं ली गयी! और उसका कितना बड़ा दुष्परिणाम हुआ! मुझे साक्ष्य मिले हैं कि मेरे बेटे ने खुद 22 जून को कहा था कि उसकी चेतना लुप्त हो रही है! और इस पर सरकार ने क्या किया? चिकित्सा सुविधा पहुंचने में अत्यदिक देर लगा दी! यहाँ तक कि उसके दोनों सहयोगियों को, जिनको कि उसके साथ बधंक बनाया गया था, उनको भी उसके साथ अस्पताल जाने नहीं दिया गया! यह सब पदाधिकारियों के निर्दयी व्यवहार के कुछ ज्वलंत उदाहरण हैं! सरकार और डॉक्टरों की जिम्मेदारी खत्म या कम नहीं हो जाती, केवल मेरे बेटे द्वारा लिखे गए पत्रों में कहीं से भी लिखी हुयी सन्दर्भहीन कुछ पंक्तियाँ दिखा कर! वह सिद्ध करने

के लिए की वह ठीक नहीं चल रहा था! ऐसी सन्दर्भहीन पंक्तियों का मूल्य क्या है? क्या कोई मेरे बेटे जैसे इंसान से यह अपेक्षा कर सकता है कि उसके जैसा व्यक्ति जेल में अपने प्रियजनों से दूर होने पर अपने मनोभाव ऐसे पत्रों में लिख कर व्यक्त करेगा या फिर स्वयं ही अपने रोग के लक्षण की पहचान कर लेगा? राज्य सरकार की जिम्मेदारी बहुत ही विशाल और गंभीर है!

मैं आरोप लगाती हूँ कि सरकार ने अपने कर्त्तव्य निभाने में उपेक्षा की है और वह जिस कर्त्तव्य के लिए वह बाध्य थे उसे निभाने में पूरी तरह असफल रहे हैं! आप बता रहे हैं कि मेरे बेटे को बंधक रखने के दौरान क्या क्या सुविधा और आराम दिए गए! इस बात की तो जांच होनी चाहिए! कश्मीर सरकार ने तो उसके परिवार से होने वाले पत्र व्यवहार तक पर प्रतिबन्ध लगा दिया था! उसके पत्र कब्जे में ले लिए गए थे और कुछ तो रहस्यमय तरीके से गायब भी हो गए! उसकी बीमार बेटी और माँ की खबर जानने की व्याकुलता काफी दुःख पूर्ण है!

क्या आपको आश्चर्य होगा की उसके द्वारा 15 जून को लिखे गए पत्र मुझे 27 जून को मिले जो कि 24 जून को कश्मीर सरकार द्वारा भेजे गए! उसकी मृत्यु के ठीक एक दिन बाद, उसकी लाश भेजने के बाद! इस पैकेट में वह पत्र भी थे जो कि मैंने और अन्य परिवार के लोगों ने श्यामा प्रसाद को लिखे थे और जिनके श्रीनगर पहुचने कि तारिख क्रमशः 11 और 16 जून छपी है परन्तु वह पत्र श्यामा प्रसाद तक पहुंचे ही नहीं! यह एक मानसिक यातना का मामला है! वह बार बार चलने फिरने के लिए पर्याप्त जगह की माँग कर रहा था! जो कि उसे नहीं दी जा रही थी जिससे उसे बीमारी का अनुभव हो रहा था! क्या यह एक तरीके से शारीरिक यातना नहीं है? मुझे आप के द्वारा कहे हुए शब्दों पर आश्चर्य होता है और शर्म भी आती है! आपने कहा था कि मेरे बेटा श्रीनगर की मशहूर डल झील के किनारे एक निजी विला में रखा गया है! जबकि उसे एक छोटी सी जगह में रात दिन सशस्त्र दस्ते की निगरानी में रखा गया था! वैसे भी क्या कोई सोने का पिंजरा किसी कैदी को खुश रख सकता है? मुझे सिहरन होती है जब ऐसा निराश करने वाला प्रचार सुनती हूँ! बाकी, चिकित्सा और सहायता क्या दी गयी यह तो मुझे मालूम ही नहीं है! सरकारी रिपोर्ट में आपस में ही काफी विरोधाभास है! बड़े बड़े चिकित्सकों की यही राय है कि मेरे बेटे के स्वास्थ्य के साथ घोर अपेक्षा हुयी है! मैं इस मामले की गहन और निष्पक्ष जांच चाहती हूँ!

मैं यहाँ इस पत्र द्वारा अपने बेटे की मौत का विलाप नहीं कर रही हूँ! वह इस आजाद भारत का निडर सपूत था जिसकी कैद में बिना कोई सुनवाई हुए मृत्यु हो गयी है और वह भी इतनी दुर्भाग्यपूर्ण और रहस्य से भरी हुयी! मैं उस महान आत्मा की माँ होने के नाते यह माँग करती हूँ कि जल्दी से जल्दी इस मामले की निर्दलीय और कुशल लोगों द्वारा एक निष्पक्ष और खुली जांच करायी जाये! मुझे मालूम है कि जिसे हमने खोया है उसे हम कभी वापस नहीं पा सकते! लेकिन मैं यह अवश्य चाहती हूँ कि भारत के लोग स्वयं इस बात का निर्धारण करें कि आजाद देश में किन कारणों से यह महान दुर्घटना हुयी और इसमें आपकी खुद की सरकार का क्या हाथ था!

चाहे किसी के भी साथ कोई गलत बात होती है... चाहे गलती करने वाला कोई भी क्यूँ न हो... बड़े से बड़ा, न्याय तो होना ही चाहिए ताकि लोग सावधान हो जायें और इस आजाद भारत में उन्हें दुःख और संताप के आंसू न बहाने पड़ें जैसे कि मुझे बहाने पड़ रहे हैं!

यह बहुत अच्छी बात है कि आपने मुझसे कहा कि मैं आपको आपके लायक सेवा बता दूं! तो मेरी यही माँग है अपने बेटे की ओर से और भारत की तमाम माओं की ओर से भी! भगवान आपको इतनी शक्ति दे कि आप सच को बाहर सबके सामने आने दें!

पत्र समाप्त करने से पहले मैं आपको एक बहुत महत्पूर्ण बात बताना चाहूंगी कि श्यामा प्रसाद कि निजी डायरी और हाथ के लिखे अन्य कागज तथा उसका अन्य निजी सामान मुझे कश्मीर सरकार ने अभी तक नहीं भेजा है! मेरे बड़े बेटे राम प्रसाद और बख्शी गुलाम मोहम्मद के बीच हुए सारे पत्रव्यवहार में इस पत्र के साथ भेज रही हूँ! मैं आभारी होऊंगी अगर आप मेरे बेटे कि डायरी और हाथ के लिखे अन्य कागज आप मुझे कश्मीर सरकार से दिला सकें! वह अभी उन्ही के पास होंगे!

शुभकामनाओं सहित,

संतप्त,

जोगमाया देबी

संग्राम कांग्रेस के प्रणव मुखर्जी व निर्दलीय पी ए संगमा के बीच

भाजपा, अकाली दल, अगप व मिजो फ्रंट भी संगमा के समर्थन में

& vEck pj.k of'k"B

jाष्ट्रपति पद के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी व राजग में उसके सहयोगी शिरोमणि अकाली दल ने लोक सभा के पूर्व अध्यक्ष एवं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पूर्व नेता श्री पी ए संगमा को अपना समर्थन देकर इस चुनाव को रोचक

बना दिया है। श्री संगमा ने राकांपा से त्यागपत्र दे दिया है। भाजपा के समर्थन के बाद श्री संगमा के समर्थन में कूदने वालों की संख्या बराबर बढ़ती जा रही है। असम गण परिषद व मिजो नैशनल फ्रंट ने भी श्री संगमा को समर्थन देने की घोषणा कर दी है।

श्री संगमा एक प्रतिष्ठित जनजातीय नेता हैं जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न पदों को शोभा देकर राष्ट्रव्यापी ख्याति प्राप्त की है। राष्ट्रपति पद के लिये उनके नाम का प्रस्ताव तमिलनाडू की मुख्यमन्त्री सुश्री जयललिता व ओडिशा के मुख्यमन्त्री श्री नवीन पटनायक ने पहले ही कर रखा है।

राष्ट्रपति पद के लिये अपना प्रत्याशी तय करने के लिये राष्ट्रीय जनतान्त्रिक गठबन्धन की कई बैठकें हुईं पर कोई एक राय न बन पाई। अन्ततः भाजपा ने निर्णय लिया कि वह कांग्रेस प्रत्याशी को वाक–ओवर नहीं दे सकती और देश के अग्रणी विपक्षी दल का दायित्व निभाते हुये निर्दलीय प्रत्याशी श्री पी ए संगमा का समर्थन करेगी क्योंकि वह इस सम्मानित पद के लिये उपयुक्त प्रत्याशी हैं। लोक सभा में प्रतिपक्ष की नेता श्रीमती सुषमा स्वराज व राज्यसभा में प्रतिपक्ष के नेता श्री अरूण जेतली ने इस निर्णय की घोषणा एक सांझे पत्रकार सम्मेलन को सम्बोधित करते हुये की। उन्होंने खेद प्रकट किया कि इस मुददे पर राजग के सभी घटकों में आम सहमति नहीं बन पाई।

दोनों नेताओं ने स्पष्ट किया कि इस एक विषय पर सहमति के अभाव में भी राजग गठबन्धन यथावत इकट्ठा और सशक्त है। ऐसे ही विचार व भावना जनता दल युनाईटेड के अध्यक्ष एवं राजग संयोजक श्री शरद यादव ने व्यक्त किये हैं।

श्रीमती सुषमा स्वराज ने कहा कि भाजपा व राजग राष्ट्रपति पद के लिये व्यापक सहमति के आधार पर एक सांझे सर्वमान्य प्रत्याशी के पक्ष में थी पर कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी घोषित करने से पूर्व राजग व भाजपा से कोई चर्चा नहीं की। श्री मुखर्जी को अपना प्रत्याशी घोषित करने के बाद प्रधानमन्त्री ने भाजपा संसदीय दल के अध्यक्ष श्री लालकृष्ण आडवाणी को अपने प्रत्याशी की सूचना दी और भाजपा से समर्थन का आग्रह किया जिसे पार्टी ने अस्वीकार कर दिया।

यदि कांग्रेस सचमुच ही इस चुनाव में आम सहमति बनाना चाहती होती तो उसे अपना प्रत्याशी घोषित करने से पूर्व राजग से विचार–विमर्श करना चाहिये था। राजग महामहिम का वफादार विपक्ष तो है नहीं कि वह जो भी नाम सुझा दे उस पर राजग बिना विचार किये आंख मूंद कर अपना अंगूठा लगा दे।

श्री अरूण जेतली ने स्पष्ट किया कि चुनाव जनतन्त्र की एक अनिवार्य प्रक्रिया है और भाजपा उस पर ही चल

आज आम आदमी का जीवन दूभर हो गया है। उसके लिये पूरी सरकार व कांग्रेस के साथ–साथ वर्तमान वित्तमन्त्री श्री प्रणव मुखर्जी भी जिम्मेवार हैं। इस स्थिति में विपक्षी दलों द्वारा वित्तमन्त्री को राष्ट्रपति पद के लिये समर्थन देना संप्रग सरकार व श्री मुखर्जी की विफलताओं में सहभागी बन जाना हो जाता। इस प्रकार भाजपा ने श्री संगमा का समर्थन कर विपक्ष के सकारात्मक प्रतिरोध की परिपाटी को बनाये रखा है।

रही है। अब तक केवल एक ही बार 1977 में श्री नीलम संजीव रेडडी निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गये हैं। बाकी सब राष्ट्रपति चुनावी प्रक्रिया से ही चुने गये थे। भारतीय जनता पार्टी विपक्षी दल के सिद्धान्त के चरित्र को बनाये रखना चाहती है और सरकार को छूट नहीं देना चाहती जिसने अपने प्रत्याशी के लिये समर्थन जुटाने में साम–दाम–दण्ड–भेद के सब हथकण्डों को इस्तेमाल किया है। भाजपा ने कहा है कि यूपीए सरकार पूरी तरह विफल रही है और जनता से अलग–थलग पड़ गई है। हाल ही के विधान सभा चुनावों व उपचुनावों के परिणामों ने इस ओर स्पष्ट संकेत दे दिये है।

कांग्रेस नीत संप्रग सरकार के कारण देश की अर्थव्यंवस्था चरमरा गई है। रूपये की कीमत आज तक के सब से कम दाम पर पहुंच गई है और प्रतिदिन कम होती जा रही है। उसका लाभ विदेशों को है। महंगाई और मुद्रास्फीति आसमान छू रही है। मन्दी, उद्योग व कृषि उत्पाद दर घट रही है। सकल घरेलू उत्पाद कम हो रहा है। उपर से देश की आर्थिक साख गिरने की रिपोर्टें लगातार आ रही हैं। आम आदमी का जीवन दूभर हो गया है। उसके लिये पूरी सरकार व कांग्रेस के साथ–साथ वर्तमान वित्तमन्त्री श्री प्रणव मुखर्जी भी जिम्मेवार हैं। इस स्थिति में विपक्षी दलों द्वारा वित्तमन्त्री को राष्ट्रपति पद के लिये समर्थन देना संप्रग सरकार व श्री मुखर्जी की विफलताओं में सहभागी बन जाना हो जाता। इस प्रकार भाजपा ने श्री संगमा का समर्थन कर विपक्ष के सकारात्मक प्रतिरोध की परिपाटी को बनाये रखा है।

भाजपा ने सभी राजनैतिक दलों, सांसदों व विधायकों से अनुरोध किया है कि वह श्री संगमा को समर्थन देकर उन्हें सफल बनायें। ■

भाजपा ने किया पी.ए. संगमा की उम्मीदवारी का समर्थन

लोकसभा में विपक्ष की नेता श्रीमती सुषमा स्वराज और राज्य सभा में विपक्ष के नेता श्री अरूण जेटली ने 21 जून, 2012 को नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में राष्ट्रपति पद के लिए श्री पी.ए. संगमा की उम्मीदवारी के समर्थन की घोषणा की।

भारत के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए तमिलनाडु की मुख्यमंत्री सुश्री जे. जयललिता और ओडीशा के मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक ने पूर्व लोकसभा अध्यक्ष पी. ए. संगमा के नाम का प्रस्ताव रखा है। भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए के घटक दलों, अन्य राजनैतिक पार्टियों तथा कुछ राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कई बार विचार–विमर्श किया। भारतीय जनता पार्टी की आम सहमति बनी है कि चुनाव लड़ा जाए और श्री पी.ए. संगमा की उम्मीदवारी का समर्थन किया जाए। हमें इस बात का दुख है कि एनडीए के कुछ मित्रों ने इस विचार में हमारा साथ नहीं दिया।

चुनाव लड़ने के हमारे फैसले के पीछे कई कारण हैं :

- यूपीए ने विपक्ष के साथ इस मुद्दे पर पहले विचार–विमर्श नहीं किया। विपक्ष को उम्मीदवार की घोषणा करने के बाद केवल सूचित किया गया और उनकी मर्जी के हिसाब से समर्थन करने को कहा गया। कई ने उनकी हां में हां मिला दी और अनेक ने उनका साथ देने से इंकार कर दिया।
- भारत के अधिकतर राष्ट्रपति चुनाव के बाद ही चुने गए हैं। चुनाव का विचार लोकतंत्र का हिस्सा है, कोई अनजाना विचार नहीं।
- भारतीय जनता पार्टी विपक्षी दल के सिद्धांत के चरित्र को बनाए रखना चाहती है और सरकार को छूट नहीं देना चाहती, जिसने समर्थन जुटाने के लिए साम–दाम–दंड–भेद का इस्तेमाल किया है। यूपीए–II सरकार शासन करने में विफल रही है।
- सत्तारूढ़ यूपीए गठबंधन जनता से पूरी तरह अलग–थलग पड़ गया है। हाल के चुनावों में इसके संकेत भी देखने को मिले हैं। लेकिन जांच एजेंसियों का दुरूपयोग कर वह कुछ राजनैतिक वर्गों से अपना काम निकालने में सफल रही है।

भारतीय जनता पार्टी ने भारत के राष्ट्रपति पद के लिए श्री पी.ए. संगमा की उम्मीदवारी का समर्थन करने का निर्णय लिया है। हमारी सभी राजनैतिक दलों, सांसदों और विधायकों से अपील है कि वे श्री संगमा का समर्थन करें और इस चुनाव में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का परिचय दें। ■

समस्या सुलझाने की बजाय और उलझाने का प्रयास

&latho d|ekj flUgk

jkष्ट्र 'बुद्धिजीवियों' के थोथे तर्कों से नहीं चलता। यह पूर्वग्रहों से नहीं चलता। यह प्रतिक्रियाओं से नहीं चलता। यह धमकियों से नहीं चलता। यह तुष्टीकरण की नीतियों से नहीं चलता। यह जोड़–तोड़ से नहीं चलता। यह वास्तविक धरातल की अनदेखी से नहीं चलता। यह जन से कटकर नहीं चलता। राष्ट्र चलता है राष्ट्रीय भावना से। अपने गौरवशाली परंपरा के प्रति गर्वोन्नत भावना से। उस भूमि के प्रति मातृवत् भाव से। ठोस वास्तविक धरातल के अवलोकन से। राष्ट्रीय एकता और अखंडतार्थ सजगता से। अलगाववादी प्रवृत्ति पर मर्मांतक प्रहार से।

गत महीने जम्मू–कश्मीर पर वार्ताकारों की रिपोर्ट सार्वजनिक हुई। इस रिपोर्ट ने राज्य की समस्याएं सुलझाने की बजाए और उलझा दिया है। यह रिपोर्ट राष्ट्रीय भावना के खिलाफ है। इसमें राष्ट्रीय हित के साथ समझौता किया गया है। इसमें अलगाववाद का पोषण है। इसमें अनुच्छेद 370 को 'अस्थायी' के बजाय 'विशेष' बनाने की बात कई गई है। इसमें जम्मू और लद्दाख क्षेत्र उपेक्षित है। इसमें विस्थापित कश्मीरी हिंदुओं के पुनर्वास की ठोस पहल नहीं है।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघचालक प.पू. श्री गुरुजी अपने प्रबोधनों में अक्सर एक बोधकथा सुनाते थे। यह कथा इस रिपोर्ट पर सटीक बैठती है। ''एक बार प्राणिविज्ञान के छात्रों को मजाक सूझा। उन्होंने किसी कीड़े का मुँह, किसी का पेट, किसी का पैर और किसी के पंख आदि को जोड़कर एक कीड़े जैसा आकार दे दिया। फिर उसे प्रयोगशाला की मेज पर रख दिया। कुछ देर बाद जब उनके अध्यापक आये, तो छात्रों ने कहा कि यह अजीब सा कीड़ा उन्होंने पकड़ा है। कृपया इसका नाम बताकर इस वर्ग की विशेषताएँ बतायें। अध्यापक छात्रों का मजाक समझ गये। वे बोले – यह कीड़ा या कीड़ी नहीं, धोखाधड़ी है।'' जम्मू–कश्मीर पर वार्ताकारों की रिपोर्ट भी राष्ट्र के साथ धोखाधड़ी है। इस रिपोर्ट के बारे में कहा जा सकता है, 'कहीं का ईंट, कहीं का रोड़ा; भानुमती ने कुनबा जोड़ा।'

देश की आजादी के समय से ही जम्मू–कश्मीर अशांत है। सन् 2010 में राज्य में पत्थरबाजी की घटना हुई। इसी परिदृश्य में केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने जम्मू और कश्मीर में स्थायी शांति, स्थिरता और खुशहाली को सुनिश्चित करने और कश्मीर मुद्दे का व्यापक राजनीतिक समाधान निकालने के लिए तीन वार्ताकारों के एक दल का गठन किया। वार्ताकारों के दल ने 'जम्मू और कश्मीर की जनता के साथ एक नया समझौता (ए न्यू कांपैक्ट विथ द पीपुल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर) नाम से रिपोर्ट बनाई। वार्ताकारों ने कुल 11 बार राज्य का दौरा किया और राज्य के सभी जिलों में प्रवास किया। उन्होंने 22 जिलों में 700 से अधिक प्रतिनिधियों से बात की और तीन गोलमेज़ सम्मेलनों में समूहों के साथ वार्ता की। वार्ताकारों ने राज्यपाल एनएन बोहरा, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती और अन्य राजनीतिक पार्टियों के नेताओं, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों, पत्रकारों और विभिन्न वर्गों के लोगों से व्यापक बातचीत की। जबकि कश्मीर के अलगाववादी नेताओं ने इन वार्ताकारों से मिलने तक से इनकार कर दिया।

विदित हो कि महाराजा हरिसिंह की लिखित सहमति से जम्मू–कश्मीर

क्या है उद्देश्य ?

केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जम्मू और कश्मीर के लिए तीन वार्ताकारों के एक दल का गठन। इस दल का उद्देश्य था जम्मू–कश्मीर में स्थायी शांति, स्थिरता और खुशहाली के लिए समाधान ढूंढ़ना।

कौन-कौन हैं वार्ताकार ?

तीन सदस्यीय वार्ताकार हैं– वरिष्ठ पत्रकार दिलीप पडगांवकर, शिक्षाविद् राधाकुमार और पूर्व केन्द्रीय सूचना आयुक्त एम.एम. अंसारी।

गठन कब हुआ ?

13 अक्टूबर 2010 को केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने जम्मू–कश्मीर पर वार्ताकारों के दल का गठन किया।

रिपोर्ट कब सौंपी ?

12 अक्टूबर 2011 को वार्ताकारों के दल ने केन्द्रीय गृह मंत्री श्री पी. चिदम्बरम को 176 पृष्ठ की रिपोर्ट सौंपी।

रिपोर्ट कब सार्वजनिक हुई ?

सात महीने बाद 24 मई 2012 को यह रिपोर्ट सार्वजनिक हुई।

का भारत में विलय हुआ। इसके पश्चात् राज्य की बागडोर शेख अब्दुल्ला के हाथों में आ गई। उसने राज्य में अस्थिरता और अराजकता का हवाला देते हुए कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने में सफलता पा ली। इस विशेष दर्जा के चलते हुआ यह कि कश्मीर में प्रवेश करने के लिए परमिट लेने का कानून भी बनाया गया। पूरे देश में इसके खिलाफ जनाक्रोश उभरा। भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस जनाक्रोश को मुखरित किया। डॉ. मुखर्जी की सोच थी कि पूरा भारत एक राष्ट्र है तो फिर जम्मू–कश्मीर में जाने के लिए परमिट का प्रावधान क्यों? उन्होंने तय किया कि वे बिना परमिट के राज्य में प्रवेश करेंगे। 'एक देश में दो प्रधान, दो विधान और दो निशान–नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे' इस नारे का उद्घोष करते हुए डॉ. मुखर्जी पठानकोट के रास्ते जम्मू की सीमा में पहुंचे। यहां पर पुलिस ने उन्हें गिरतार कर नजरबंद कर दिया। नजरबंदी के 43वें दिन अर्थात् 23 जून 1953 को उनका देहावसान हो गया। और इस तरह डॉ. मुखर्जी स्वतंत्र भारत के ऐसे पहले अमर शहीद हुए, जिन्होंने राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए

प्रमुख सिफारिशें

- संविधान के अनुच्छेद 370 के शीर्षक और भाग ग्ग् के शीर्षक से 'अस्थायी' शब्द हटाना। इसके बजाए अनुच्छेद 371 (महाराष्ट्र और गुजरात), अनुच्छेद 371–ए (नागालैण्ड), अनुच्छेद 371–बी (असम), अनुच्छेद 371–सी (मणिपुर), अनुच्छेद 371–डी और ई (आन्ध्र प्रदेश), अनुच्छेद 371–एफ (सिक्किम), अनुच्छेद 371–जी (मिज़ोरम), अनुच्छेद 371–एच (अरुणाचल प्रदेश), अनुच्छेद 371–आई (गोवा) के अधीन अन्य राज्यों की तर्ज पर 'विशेष' शब्द रखा जाए।
- राज्यपाल के चयन के लिए राज्य सरकार विपक्षी पार्टियों से परामर्श करके राष्ट्रपति को तीन नाम भेजेगी। आवश्यक होने पर राष्ट्रपति अधिक सुझाव माँग सकते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और वह राष्ट्रपति जी की कृपा से पदधारण करेगा।
- अनुच्छेद 356 : वर्तमान में राज्यपाल की कार्रवाई को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। वर्तमान व्यवस्था इस परन्तुक के साथ जारी रह सकती है कि राज्यपाल राज्य विधानमण्डल को निलम्बित अवस्था में रखेगा और तीन महीने के भीतर नए चुनाव कराएगा।
- अनुच्छेद 312 : अखिल भारतीय सेवाओं से लिए जा रहे अधिकारियों का अनुपात धीरे–धीरे कम किया जाएगा और प्रशासनिक दक्षता में रुकावट बिना राज्य की सिविल सेवा से लिए जाने वाले अधिकारियों की संख्या बढ़ाई जाएगी।
- अंग्रेजी में गवर्नर और मुख्यमंत्री के नाम जैसे आज हैं वैसे ही रहेंगे। उर्दू प्रयोग के दौरान उर्दू पर्यायवाची शब्द इस्तेमाल किए जा सकते हैं।
- तीन क्षेत्रीय परिषदें बनाना , जम्मू, कश्मीर और लद्दाख के लिए अलग–अलग (लद्दाख आगे से कश्मीर का एक मण्डल नहीं रहेगा)। उन्हें कुछ विधायी, कार्यकारी और वित्तीय शक्तियां दी जाएं। समग्र पैकेज के भाग के रूप में पंचायती राज संस्थाओं को राज्य के स्तर पर, ग्राम पंचायत, नगर–पालिका परिषद या निगम के स्तर पर कार्यकारी और वित्तीय शक्तियां भी देनी होंगी। ये सब निकाय निर्वाचित होंगे। महिलाओं, अनुसूचित जाति/जनजाति, पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान होंगे।
- विधायक पदेन सदस्य होंगे, जिन्हें मतदान का अधिकार होगा।
- संसद राज्य के लिए कोई कानून तब तक नहीं बनाएगी जब तक इसका संबंध देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा से और इसके महत्वपूर्ण आर्थिक हित, विशेषतः ऊर्जा और जल संसाधनों की उपलब्धि के मामलों से न हो।
- पूर्व शाही रियासत के सब भागों में ये परिवर्तन समान रूप से लागू होने चाहिए। नियंत्रण रेखा के आर–पार सहयोग के लिए सब अवसरों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इसके लिए पाकिस्तान नियंत्रित जम्मू और कश्मीर में पर्याप्त सांविधानिक परिवर्तन आवश्यक होंगे।
- सब कश्मीरियों, मुख्यतः पंडितों (हिन्दू अल्पसंख्यक) की राज्य नीति के भाग के तौर पर वापसी सुनिश्चित करना।
- नियंत्रण रेखा के आरपार लोगों, वस्तुओं व सेवाओं की आवाजाही की खुली छूट मिले।
- सेना व अर्द्धसैनिक बलों की संख्या घटाई जाए और उन्हें मिले विशेषाधिकार वापस लिए जाएं।
- बातचीत में अलगाववादियों, आतंकवादियों व पाकिस्तान समेत सभी पक्षों को शामिल किया जाए।

अपना बलिदान दिया।

जम्मू–कश्मीर समस्या को लेकर भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय दृष्टिकोण सर्वविदित है। राष्ट्रीय एकता और अखण्डता को सुनिश्चित करना पार्टी की विचारधारा है। गत मई माह में मुंबई में संपन्न भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में पार्टी ने वार्ताकारों की ओर से प्रस्तुत की गई रिपोर्ट को खारिज कर दिया। राज्यसभा में विपक्ष के नेता श्री अरुण जेटली ने इस रिपोर्ट को शब्दाडम्बरपूर्ण दस्तावेज करार देते हुए कहा कि इसमें आधारभूत वास्तविकताओं को नकारा गया है। उन्होंने चिंता जताते हुए कहा कि इस रिपोर्ट में भारत की संसद में पारित 1994 के प्रस्ताव में स्वीकृत पाकिस्तान अधिकृत काश्मीर (पीओके) को भारत के अभिन्न अंग सम्बन्धी भारतीय स्थिति को कमजोर कर दिया गया है। यह रिपोर्ट इस आधार पर तैयार की गई है कि पीओके क्षेत्र का प्रशासन पाकिस्तान करता है और करता रहेगा तथा इसमें पीओके को पीएके (पाकिस्तान प्रशासित जम्मू और काश्मीर) के रूप में उल्लेख किया गया है।

गौरतलब है कि जम्मू–कश्मीर के भारत में विलय के दौरान इसे संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। यह अनुच्छेद राष्ट्रीय एकता और अखंडता में बाधक है। शेष भारत में इस अनुच्छेद को लेकर लोगों में गुस्सा है। जबकि इस रिपोर्ट में वार्ताकार इस विशेष दर्जे को बनाए रखने की बात ही नहीं करते अपितु इसके साथ लगे 'अस्थायी' शब्द की जगह 'विशेष' शब्द लिखने की भी सिफारिश करते हैं। यह रिपोर्ट अपने ही देश में शरणार्थी बने हुए कश्मीरी हिंदुओं की समस्याओं को गंभीरता से नहीं लेता, इसका अंदाजा इसी बात से लग जाता है कि रिपोर्ट के कुल 176 पृष्ठों में केवल दो पृष्ठ सामग्री भी कश्मीरी हिंदुओं को नहीं दी गई है। इसी तरह जम्मू–कश्मीर में आतंकवाद एक प्रमुख चुनौती है, लेकिन वार्ताकारों ने इसके तह में भी जाने की कोशिश नहीं की है और न ही इसे खत्म करने के लिए कोई कारगर उपाय बताते हैं।

कांग्रेसनीत यूपीए सरकार के गृहमंत्रालय द्वारा जम्मू–कश्मीर पर गठित वार्ताकारों के दल ने कांग्रेस की तरह ही ढुलमूल नीतियां बनाने की सिफारिश की है। इसकी चहुंओर आलोचना हो रही है। राष्ट्रवादी राजनैतिक दलों एवं संगठनों की ओर बुलंद होते आवाज की प्रखरता को देखते हुए गृहमंत्रालय भी अब इसे स्वीकारने से हिचक रही है। इससे साफ है कि जम्मू–कश्मीर समस्या पर अपने ढुलमूल रवैय्ये के लिए जनविश्वास का कोपभाजन बनी सरकार अपने हाथ नहीं जलाना चाहती। ■

पृष्ठ 13 का शेष...

इस पर, पुलिस अधिकारी ने पब्लिक सेफ्टी एक्ट के अन्तर्गत गिरफ्तारी का आदेश निकाला और डॉ. मुकर्जी को हिरासत में ले लिया। उस दल में वैद्य गुरुदत्त और टेकचंद दो सहयोगी थे, जो डॉ. मुकर्जी की गिरफ्तारी के समय उनके साथ थे। उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। तब डॉ. मुकर्जी ने अटल से बात की और उन्हें वापस जाने को कहा तथा देश के लोगों को बताने को कहा कि डॉ. मुकर्जी ने निषेध आदेशों का तोड़ा है और बिना परमिट के जम्मू और काश्मीर में एक कैदी बनकर घुस गए हैं। जिस कारागार में डॉ. मुकर्जी को रखा गया, वह श्रीनगर से बहुत दूर निशात बाग के नजदीक एक छोटा सा घर था। इस घर को उप–जेल में बदल दिया गया था।

23 जून, 1953 को पूरे देश को यह जानकर अचम्भा हुआ कि अपने कैद के स्थान पर संक्षिप्त बीमारी के बाद डॉ. मुकर्जी को लगभग दस मील दूर स्टेट हास्पीटल में भेजा गया, जहां उन्होंने अंतिम सांसें लीं।

उस समय मैं जयपुर में था। मुझे अच्छी तरह से याद है कि उस समय 24 जून के बहुत तड़के 4.30 बजे, मैं नींद से उठा ही था कि मुझे चौरा रास्ता के हमारे पार्टी कार्यालय के बाहर कोई व्यक्ति विलाप करते हुए (जो कोई एक स्थानीय न्यूजमैन था) चिल्ला रहा था कि ''आडवाणी जी, उन्होंने डॉ. मुकर्जी की हत्या कर दी।''

तथागत राय पश्चिम बंगाल के हमारे प्रमुख कार्यकर्ता हैं। एक समय वह राज्य इकाई के अध्यक्ष भी रहे हैं। उन्होंने डॉ. श्यामा प्रसाद मुकर्जी की 'सम्पूर्ण आत्मकथा' लिखी है। इसका विमोचन अगले महीने होगा। आज हम भाजपा के लोगों का भारतीय राजनीति में जो स्थान है, उसका श्रेय हम लोगों से पूर्व के उन हजारों–हजारों कार्यकर्ताओं के बलिदान और शक्तिशाली प्रयासों को ही जाता है, और इससे भी कहीं अधिक बढ़ कर डॉ. मुकर्जी के विजन और बलिदान का फल है। हमने अपने महान नेता को बहुत करीब से केवल उनके जीवन के अंतिम वर्षों में ही जान पाया था। तथागत राय ने इतिहास और राष्ट्रीय हित में वह महान सेवा की है जिससे हम उस राजनीति का अनुकरण कर रहे हैं और उन्होंने हर प्रकार का आवश्यक शोध करके तथा उस महान देशभक्त के जन्म से लेकर पूर्ण जीवन तक के वृत्त को तैयार कर पाठकों तक पहुंचाया है। तथागत राय को शाबास ही शाबास! ■

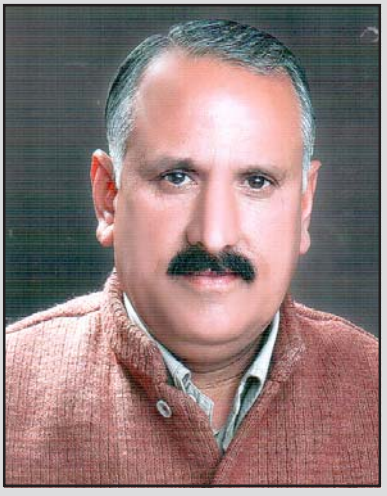

वार्ताकारों की रिपोर्ट दुर्भाग्यपूर्ण राज्य के तीनों क्षेत्रों के समुचित विकास के लिए भाजपा संघर्षरत रहेगी : शमशेर सिंह मन्हास

जम्मू और काश्मीर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष श्री शमशेर सिंह मन्हास के नेतृत्व में भाजपा ने जम्मू और कश्मीर के लोगों को प्रभावित करने वाले प्रत्येक मुद्दे पर अपनी आवाज बुलंद की है और साथ ही साथ ऐसे सभी प्रयासों का जमकर विरोध किया है जिनका उद्देश्य देश की एकता और अखण्डता को कमजोर करना रहा हो। हाल ही में भाजपा ने सम्पूर्ण लोकतांत्रिक माध्यम अपनाते हुए अथक संघर्ष का बिगुल बजा कर उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में चल रहे गठबंधन की विफलताओं को उजागर किया और लोगों की आवश्यक सेवाओं, भ्रष्टाचार और अपराध खत्म करने, क्षेत्रीय भेदभाव मिटाने, बेरोजगारी, शरणार्थियों की दुर्दशा, उग्रवाद, नागरिकों के अधिकार, राज्य के प्रति बरती जा रही केन्द्र सरकार की उपेक्षा, अमरनाथ यात्रा में समय की कटौती और जम्मू–कश्मीर वार्ताकारों की पेश की गई रिपोर्ट तथा अन्य ऐसे अनेक मुद्दों को सामने लाने का प्रयास किया गया है।

कमल संदेश के लिए सम्पादकीय मण्डल के सदस्य Jh jkeçlkn f=ikBh *ने श्री मन्हास से साक्षात्कार किया, जिसमें उन्होंने बताया कि वार्ताकारों की रिपोर्ट में अनेक गम्भीर त्रुटियां है और इसकी घोर निंदा करते हुए कहा कि इसमें ऐसा प्रयास किया जा रहा है जिससे राज्य फिर से 1953 की पूर्व स्थिति पर पहुंच जाए। उन्होंने इस बात की भी भर्त्सना की कि राज्य सरकार घाटी से हिन्दू धर्म के सभी चिह्नों और प्रतीकों को मिटा कर विश्वभर के करोड़ों हिन्दुओं की भावनाओं का निरादर और मटियामेट करने पर उतारू है। साक्षात्कार के कुछ प्रमुख उद्धरण प्रस्तुत हैं:*

- श्री दिलीप पडगांवकर के नेतृत्व में जम्मू और काश्मीर वार्ताकारों की रिपोर्ट हाल ही में पेश की गई है। आप इस रिपोर्ट को किस दृष्टि से देखते हैं और इस पर भाजपा का क्या दृष्टिकोण है? क्या आप राज्य को और अधिक स्वायत्तता देने के प्रस्ताव से सहमत हैं? क्या इससे जम्मू और काश्मीर की दीर्घकाल से चली आ रही समस्याओं का समाधान हो सकेगा?

मैं इस रिपोर्ट को, वादी के उन स्थानीय उग्रवादियों जो पाकिस्तान से मिले हुए हैं से मिलकर एक शरारत समझता हूं जो राज्य को शेष देश से अलग करने का प्रयास कर रहे हैं। भाजपा पूरी तरह से इस रिपोर्ट को खारिज करती है क्योंकि यह राज्य को कमजोर करने और शेष देश से राज्य के बंधनों पर पानी फेरने का एक कदम है। हमारा यह दृष्टिकोण कई बार दोहराया गया है और मुम्बई में हुई हाल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में इसका समर्थन भी किया गया है। इससे आम आदमी और राज्य की समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा, बल्कि यह समस्या और अधिक गम्भीर बन जाएगी।

- जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जम्मू और काश्मीर को भारत के साथ पूरी तरह से मिलाने के लिए अपने जीवन की आहुति दे दी थी। क्या आप समझते हैं कि वार्ताकारों का यह वर्तमान प्रयास पिछले रास्ते से १९५३ से पहले की स्थिति में लाने की कोशिश नहीं है?

देश के अन्य राज्यों से हटकर जम्मू और काश्मीर राज्य शेष देश के साथ विलय होने के बाद इस राज्य का अपना संविधान, वजीरे आजम और राज्य का ध्वज था और जैसा कि आपने स्वयं कहा कि जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दो प्रधान, दो विधान और

दो निशान के प्रावधानों से लड़ने के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया था और उन्होंने माना था कि जम्मू और काश्मीर में 'प्रवेश–परमिट' की आवश्यकता एक अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण कदम है। उन्होंने अपना जीवन राज्य को एक बहुधर्मी, सेक्युलरवाद और लोकतांत्रिक भारत के और नजदीक लाने के लिए बलिदान किया था। जनसंघ के पूर्वगामी प्रजा परिषद ने जम्मू और काश्मीर को देश का अभिन्न भाग बनाने के लिए कड़ा संघर्ष किया था। तब जनसंघ बनने पर प्रजा परिषद जनसंघ की प्रदेश इकाई बन गई थी। इस प्रकार की भयानक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और राष्ट्रवाद में हमारा मूल सिद्धांत होने के नाते हम इसे खारिज करते हैं और ऐसे सभी कदमों का विरोध करते हैं जिनसे राज्य को फिर से 1953 से पहले की स्थिति में लाया जाए। वार्ताकारों की नियुक्ति का पूरा प्रयास और उनकी रिपोर्ट हर तरह से पीछे की दिशा में मोड़ने वाली बातें हैं जो मध्ययुगीन मानसिकता और प्रवृत्ति को दर्शाती हैं।

- आप अभी तक की उमर अब्दुल्ला के कार्यप्रदर्शन को किस स्तर का मानते हैं? क्या राज्य सरकार चुनावी वायदों के कार्यान्वियन में सफल रही है? क्या राज्य सरकार राज्य के तीनों भागों में विकास सुनिश्चित करने के मामले में न्याय संगत रही है?

उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में वर्तमान एनसी–कांग्रेस गठबंधन का कार्यप्रदर्शन एकदम निराशाजनक और विफल है। चुनावी वायदों को पूरा करने की बात तो बड़ी दूर की है, इसने तो आम आदमी के जीवन को आर्थिक रूप से बदतर बना दिया है और यह आम नागरिक के जान–माल की भी सुरक्षा करने में असमर्थ रही है। राज्य के तीनों क्षेत्र ही कष्ट भोग रहे हैं और जम्मू तथा लद्दाख क्षेत्रों के प्रति तो भेदभाव कहीं बढ़ चढ़कर है और विकट समस्या बन गया है।

- भाजपा ने राज्य सरकार की विफलताओं को उजागर करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

भाजपा लोगों की समस्याओं को उजागर करने के लिए जम्मू और काश्मीर में सबसे आगे है और वह निरंतर प्रयास कर रही है क्योंकि ये समस्याएं राज्य सरकार द्वारा जानबूझकर पैदा की जा रही हैं। हम अथक रूप से आवश्यक सेवाओं के प्रावधानों, भ्रष्टाचार और अपराध रोकने, क्षेत्रों के साथ अविरल पक्षपातपूर्ण व्यवहार, बेरोजगारी, शरणार्थियों की दुर्दशा, उग्रवाद, नागरिकों के अधिकार आदि जैसे हर क्षेत्र में सरकार की विफलताओं का पर्दाफाश करते रहते हैं और इस प्रयोजन के लिए हम ने धरना, सार्वजनिक रैलियां, जुलूस, भूख हड़ताल आदि जैसे लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शन के साधनों को अपनाया है।

- पिछले पांच वर्षों में अमरनाथ यात्रा को चार महीनों के स्थान पर ४५ दिन तक सीमित कर दिया है। क्या आप समझते हैं कि केन्द्र और राज्य सरकार ऐसी राजनीति अपनाकर भारत के करोड़ों लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ नहीं कर रही है।

जी हां, यह सही है; सरकार विश्व के करोड़ों हिन्दुओं की भावनाओं के प्रति असंवेदनशील है। यह स्पष्ट है कि सरकार घाटी से हिन्दू धर्म के सभी चिह्नों और प्रतीकों को मिटाने पर उतारू है।

- काश्मीरी पंडित अपने ही देश में शरणार्थियों की तरह से रह रहे हैं। केन्द्र और राज्य सरकार ने पुनर्वास के मामले पर पीछे कदम हटा लिए हैं। भाजपा पंडितों के साथ हो रहे इस अत्याचार से निपटने के लिए क्या योजना है?

भाजपा ने सदैव ही काश्मीरी पंडितों के पुनर्वास और उनके अपने घरों में सम्मानजनक रूप से वापसी के लिए संघर्ष किया है। भाजपा इन विस्थापितों के गरिमामयी भविष्य के लिए अपने मिशन को जारी रखेगी।

- क्या जम्मू और काश्मीर में एएफएसपीए की वापसी के लिए जम्मू और काश्मीर का वातावरण सही है?

नहीं, जमीनी हकीकतों को देखते हुए, हम देखते हैं राज्य के दूरदराज के क्षेत्रों और नियंत्रण रेखा पर नरसंहार करने, लोगों के जीवन को अस्त–व्यस्त करने के उद्देश्य से बड़ी संख्या में प्रशिक्षित उग्रवादी खड़े हैं, अतः इस प्रकार की स्थिति में एएफएसपीए को वापस लेना या इसे कमजोर करना बुद्धिहीनता और अविवेकपूर्णता का परिचय देने जैसा होगा।

- क्या आप समझते हैं कि केन्द्र सरकार ने राज्य के विकास पर यथोचित ध्यान दिया है?

मैं नहीं समझता कि वर्तमान राजनीतिक सत्ताधारी राज्य के विकास में काफी कुछ कर पा रहे हैं और न ही वह विकास के मामले में संतुलित और समान व्यवहार कर रहे हैं। राज्य को केवल धन जारी कर देना ही पर्याप्त नहीं है, जरूरत इस बात की भी है कि राज्य में प्रभावकारी, विश्वसनीय ढंग से इस धन का हिसाब–किताब भी मांगा जाए और यह केन्द्र का दायित्व है कि वह देखे कि राज्य में एक क्षेत्र के ऊपर दूसरे क्षेत्र के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार न हो।

शेष पृष्ठ 24 पर

खतरनाक है मल्टी ब्रांड्स रिटेल में विदेशी निवेश : राजनाथ सिंह

भारतीय जनता पार्टी, व्यापारी प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की दो दिवसीय बैठक 9 और 10 जून 2012 को गुड़गांव हरियाणा में सम्पन्न हुई। इस बैठक का उद्घाटन भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने किया। उन्होंने भाजपा को व्यापारियों की हितैषी पार्टी बताया और कहा कि वर्तमान संप्रग सरकार व्यापारी विरोधी है। उन्होंने मल्टी ब्रांड्स रिटेल में विदेशी निवेश को खतरनाक बताते हुए कहा कि भाजपा किसी भी कीमत पर ऐसा नहीं होने देगी। अगर ऐसा हुआ तो देश से खुदरा व्यापारी खत्म हो जायेंगे और विदेशी कम्पनियां

लूट शुरू कर देंगी। उन्होंने आधारभूत ढांचे में विदेशी निवेश की वकालत की। इससे पूर्व बोलते हुए व्यापारी प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक श्री उमेश अग्रवाल ने सभी भाजपा नेताओं का स्वागत किया।

व्यापारी प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय संयोजक श्री श्याम बिहारी मिश्रा ने श्री राजनाथ सिंह का स्वागत करते हुए उन्हें व्यापारी हितैषी बताया। श्री मिश्रा ने व्यापारियों की समस्याओं पर विस्तार से प्रकाश डाला उन्होंने विदेशी निवेश को छोटे व्यापारियों के हितों के खिलाफ बताया। प्रकोष्ठ के सह संयोजक श्री घनश्याम अग्रवाल ने बताया कि बैठक में लगभग सभी प्रान्तों से भाजपा नेता भाग ले रहे हैं। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रोफेसर राम बिलास शर्मा और मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष श्री कृष्ण पाल गुज्जर ने हरियाणा में व्यापारियों पर हो रहे अत्याचारों का विस्तार से जिक्र किया और कहा कि जबसे हरियाणा में कांग्रेस सरकार आयी है व्यापारियों की दिन दहाड़े हत्या हो रही है। ■

मनमोहन सबसे बेबस प्रधानमंत्री : नितिन गडकरी

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी ने कहा कि दुनियाभर में अर्थशास्त्री के रूप में पहचाने जाने वाले मनमोहन सिंह हिंदुस्तान के बेबस, असहाय और मजबूर प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि महंगाई और भ्रष्टाचार से जूझती जनता के हित में फैसले कौन लेगा?सोनिया गांधी को तो राहुल को प्रधानमंत्री बनाने की चिंता है।

गत 9 जून को गुड़गांव में भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ की दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पहले दिन हरियाणा के व्यापारियों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गडकरी ने केंद्र और प्रदेश की सरकार पर जमकर हमले किए।

उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान 'दुखियों का सागर' बन गया है। योजना आयोग को सवालों के घेरे में खड़ा करते हुए पूछा कि सोनिया, मनमोहन सिंह को बताना चाहिए कि गांव में 27 रुपए और शहर में 32 रुपए कमाने वाला अमीर कैसे है? उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति ऐसी है कि जीडीपी दर 5.2 फीसदी यानी अब तक के सबसे निचले स्तर पर है। एनडीए शासन में 38 रुपए प्रति डालर का भाव था, कब साठ रुपए हो जाए कहा नहीं जा सकता। निवेश के लिए भारत सबसे पसंदीदा स्थल था, अब निवेश कर चुके लोग भी वापस जा रहे हैं। खाद्य सुरक्षा कानून विधेयक, बेलगाम होते वस्तु एवं सेवा कर, खुदरा व्यापार में विदेशी निवेश सरीखे कानून बनाकर सरकार व्यापारियों के हौसले पस्त करने का प्रयास कर रही है।

यूपीए सरकार में हुए घोटालों पर कैग का हवाला देते हुए जम कर हमले बोले। ए राजा से लेकर गृहमंत्री पी चिदंबरम और शीला दीक्षित को कठघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि मुल्क को विकास की राह पर सिर्फ भाजपा की चला सकती है। पार्टी के लोगों से कहा मजबूती और संगठन के विस्तार के लिए कार्य करे। ■

आर्थिक सुधारों के नाम पर देश को नष्ट करने की साजिश : डॉ. जोशी

भारतीय जनता पार्टी व्यापारी प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के समापन सत्र में भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. मुरली मनोहर जोशी ने गलत आर्थिक नीतियों के लिए केंद्र सरकार को जमकर कोसते हुए आरोप लगाया कि आर्थिक सुधारों के नाम पर देश को नष्ट करने की साजिश रची जा रही है। उन्होंने खुदरा व्यापार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को सिरे से नकारते हुए इसे आम आदमी के खिलाफ षड्यंत्र करार दिया।

देश के करीब सभी प्रदेशों से आये व्यापारी नेताओं को संबोधित करते हुए डॉ. जोशी ने मनमोहन सरकार को जनविरोधी व् भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली साकार बताया। उन्होंने कहा कि यह सरकार कुछ बड़े औद्योगिक घरानों और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के इशारों पर काम कर रही है। उसे आम आदमी के हित से जुड़े मुद्दों से कोई सरोकार नहीं है। महंगाई, बेरोजगार बढ़ रही है और सरकार चंद लोगों को फायदा पहुँचाने के लिए नीतियाँ बनाने पर तुली है। उन्होंने खुदरा कारोबार में विदेशी निवेश को आम आदमी के ऊपर कुठाराघात बताया और कहा कि इससे न केवल छोटा व्यापारी तबाह हो जायेगा अपितु किसान भी विनाश के कगार पर पहुँच जायेंगे।

इस सत्र में भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री श्याम जाजू और हरियाणा भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेशी लाल, मीडिया प्रभारी राजीव जैन ने वायदा कारोबार को खतरनाक बताते हुए इस पर तुरंत प्रतिबन्ध लगाने की वकालत की। सम्मलेन में पूर्व सांसद डॉ. सुधा यादव, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रामबिलास शर्मा सहित कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे।

भाजपा नेता ने छोटे व्यापारियों को बढ़ावा देने और उन्हें नयी तकनीक से अवगत कराकर आगे बढ़ने के मौके देने की वकालत की। उन्होंने कहा कि देश में खुदरा व्यापार बीस प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है। बेरोजगारी खत्म करने का यह सबसे कारगर उपाय है। डॉ. जोशी के मुताबिक अगर खुदरा व्यापार न हो तो देश में पूंजी क्रांति हो जायेगी। उन्होंने कहा कि यदि खुदरा व्यापार को बढ़ावा दिया जाये, तो इससे न केवल कर में बढ़ोतरी होगी बल्कि रोजगार भी बढेगा। भाजपा के नेता के अनुसार यदि हिन्दुस्तान के व्यापार और व्यापारी का पतन होता है तो यह हिन्दुस्तान की आजादी और परम्परा को खत्म कर देगी। डॉ. जोशी ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम को विनाशकारी बताते हुए इसे तुरंत वापस लेने की मांग भी की। डॉ. जोशी ने कर दरों को तर्कसंगत बनाने की वकालत की। उन्होंने पेट्रोल डीजल पर निर्भरता कम करने और वैकल्पिक उर्जा उपायों को अपनाने की जरुरत पर बल दिया। इससे पूर्व प्रकोष्ठ के हरियाणा संयोजक उमेश अग्रवाल ने सभी का आभार किया और कहा कि वो व्यापारियों के हितों के लिए हमेशा संघर्ष करते रहेंगे। ■

पृष्ठ 22 का शेष...

केन्द्र सरकार पूरी तरह से अपने कर्त्तव्य और दायित्व को निभा नहीं पा रही है जिससे राज्य के बेचारे नागरिकों को केन्द्र से मिले धन का लाभ मिल सके और यह बेकार न जाए।

- भाजपा २००२ में एक सीट से बढ़कर २००८ में ११ सीटों पर पहुंच गई। आप राज्य में भाजपा के भविष्य के बारे में क्या कुछ सोचते हैं?

राज्य में भाजपा का भविष्य बहुत उज्ज्वल है। लोगों को हमसे बड़ी आशाएं हैं कि भाजपा ही उनके विचार में एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो राज्य में आम आदमी से जुड़ी समस्याओं को उठाती है और लोगों के अधिकारों के लिए संघर्ष करती है।

- जम्मू और काश्मीर पर भाजपा का क्या विजन है?

भाजपा का सपना है कि राज्य सेक्युलारिज्म, समृद्धि का दीप स्तम्भ बने और राज्य के तीनों क्षेत्रों में बराबर का विकास करते हुए यहां के नागरिकों को संतुष्टि प्राप्त हो और साथ ही राज्य के विकास में युवाओं की भागीदारी सबसे आगे बनी रहे।

- आपके शेष कार्यकाल में आपका मिशन क्या है?

भाजपा के कामकाज में नैतिकता का उच्च मानदण्ड स्थापित हो और एक बहुत बड़ा जनाधार तैयार किया जा सके जिससे भाजपा 2014 के चुनावों में प्रमुख शक्ति बन कर सामने आए। ■

किसानों को जीरो प्रतिशत पर कर्ज

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान का संकल्प है, 'खेती को फायदे का व्यापार बनाकर ही दम लूंगा' और इसके लिए वे लगातार प्रयास कर रहे हैं। हाल ही में प्रदेश सरकार ने गेहूं और धान की खरीदी पर किसानों को विशेष लाभांश दिया। इसी क्रम में उन्होंने अब इतिहास रचते हुए घोषणा की है कि किसानों को जीरो प्रतिशत पर कर्ज दिया जाएगा और इसका लाभ अप्रैल 2012 से मिलेगा। इस आशय की घोषणा 15 एवं 16 जून 2012 को 'किसान बचाओ अनुष्ठान' के तहत अपने 24 घंटे के उपवास के समापन पर मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने की।

गत 15 जून को भोपाल के बिट्ठल मार्केट स्थित दशहरा मैदान में किसान बचाओ अनुष्ठान के तहत अपने 24 घंटे के उपवास की शुरूआत करते हुए मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि केन्द्र सरकार को किसानों के मामले को लेकर एक टास्क फोर्स का गठन करना चाहिये। इस टास्क फोर्स में राज्यों के मुख्यमंत्रियों को शामिल किया जाना चाहिये ताकि वे खाद, बीज, उर्वरकों के मामले में अपनी राय दे सकें।

श्री चौहान ने कहा कि प्रत्येक रबी और खरीफ सीजन के पूर्व राज्यों से उर्वरकों की मांग बुलाई जाती है। मांग के अनुसार ही माहवार ही लक्ष्य निर्धारित किये जाते हैं। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था में अक्सर यह होता है कि जितनी डिमांड राज्य करते हैं आवंटन उससे कम होता है और दिया उससे भी कम जाता है। दाम एक साथ तय किये जायें। उन्होंने कहा कि उर्वरकों के दामों में जो वृद्धि केन्द्र ने की है उसे हमारा किसान सहने की स्थिति में नहीं है लिहाजा इसे तत्काल वापस लिया जाना चाहिये। मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार खाद पर सब्सिडी खत्म कर किसान को बाजार को भरोसे छोड़ रही है, इससे खाद के मूल्य हर महीने बढ़ेंगे और सरकार मूक दर्शक बनी देखती रहेगी।

अपने करीब आधा घंटे के भाषण में मुख्यमंत्री ने कांग्रेस को भी जमकर आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का प्रदेश की समस्याओं से कोई वास्ता नहीं है उसका एकमात्र लक्ष्य सरकार को बदनाम करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जब केन्द्र के खिलाफ आंदोलन करते थे तब संवैधानिक संकट नहीं होता था पर आज वे संवैधानिक संकट की बात कर मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। श्री चौहान ने कहा कि जनता के दर्द को लेकर उपवास करने में कोई संवैधानिक संकट नहीं होता। केन्द्र ने अगर बढ़े हुए दाम वापस न लिये तो इससे आगे भी लड़ाई जारी रहेगी।

धरने को भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, पूर्व मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा, प्रदेश संगठन महामंत्री अरविन्द मेनन, प्रदेश मुख्य प्रवक्ता बृजेश लुनावत, प्रदेश संवाद प्रमुख डॉ. हितेष वाजपेयी, वरिष्ठ मंत्री बाबूलाल गौर, उमाशंकर गुप्ता, करणसिंह वर्मा, प्रदेश प्रवक्ता

विश्वास सारंग, युवा मोर्चा राष्ट्रीय सचिव राहुल कोठारी, महापौर कृष्णा गौर, हाउसिंग बोर्ड अध्यक्ष रामपाल सिंह, खनिज निगम अध्यक्ष रामेश्वर शर्मा, बीडीए अध्यक्ष सुरेन्द्रनाथ सिंह, महापौर कृष्णा गौर ने संबोधित किया। इस अवसर पर विधायक जितेन्द्र डागा, अमरदीप मौर्य, ओम यादव, रामदयाल प्रजापति, सत्यार्थ अग्रवाल, राहुल राजपूत, सुनील पाण्डे, अनिल अग्रवाल, वंदना जाचक, कुलदीप खरे सहित पार्टी के मोर्चा, प्रकोष्ठ के पदाधिकारी उपस्थित थे।

किसानों के मुद्दे पर 24 घण्टे के उपवास पर बैठे मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 16 जून को उपवास खत्म किया। सभी धर्मगुरुओं ने उन्हें नारियल पानी पिलाकर उपवास तुड़वाया। इस मौके मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी उपवास खत्म हुआ है, लेकिन हमारा जन जागरण अभियान जारी रहेगा। अगले माह 14 जुलाई को गांव–गांव जाकर जनजागरण करेंगे। 15 जुलाई को भोपाल में महापंचायत होगी, यहां किसान अपनी बात रखेंगे। उपवास स्थल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का आंदोलन प्रतीकात्मक था, किसानों के हित में संघर्ष जारी रहेगा। आने वाले विधानसभा सत्र के दौरान खाद की कीमतों के मामले में एक संकल्प पारित किया जाएगा। उन्होंने केन्द्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली में बैठे लोगों ने कभी गांव और खेत नहीं देखे। इसलिए वे वहां बैठकर ऊटपटांग निर्णय ले रहे हैं।

उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार किसान हितैषी है, सरकार किसानों के हक में लगातार संघर्ष करती रहेगी। मुख्यमंत्री ने किसानों को सलाह दी कि वे रबी की फसल के लिए खाद उठा लें, सरकार उनसे ब्याज नहीं लेगी। फसल बीमा की भरपाई केन्द्र करे, डोडा चूरा पर लगाए गए प्रतिबंध के खिलाफ मंदसौर में आंदोलन किया जाएगा। इस मौके पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष प्रभात झा, पूर्व मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा, कैलाश जोशी एवं बाबू लाल गौर, विक्रम वर्मा, गृह मंत्री उमाशंकर गुप्ता, मंत्री करण सिंह वर्मा, हाउसिंग बोर्ड अध्यक्ष रामपाल सिंह, विधायक ध्रुव नारायण सिंह, जितेन्द्र डागा, महापौर कृष्णा गौर, मेघराज जैन सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे।■

किसानों की आवाज बनकर उभरे शिवराजसिंह चौहान- प्रभात झा

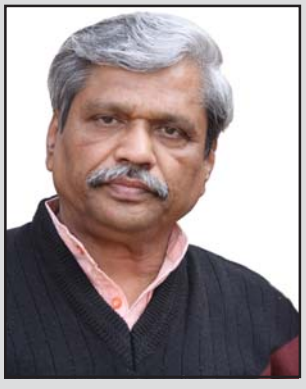

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद श्री प्रभात झा ने हजारों कार्यकर्ताओं और किसानों के साथ 'किसान बचाओ अनुष्ठान' के अवसर पर बोलते हुए कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्यप्रदेश ही नहीं देश के किसानों की आवाज बनकर उभरे है। उन्होंने केन्द्र सरकार की किसान विरोधी निरंकुश नीतियों के दंश से पीड़ित किसानों के घावों पर मरहम लगाया है। किसानों के दुख–दर्द को भारतीय जनता पार्टी समझती है। उसने भारतीय जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी के दौर में किसानों के संघर्ष का झंडा थामा है। मध्यप्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद पर जहां 850 करोड़ रू. और धान की खरीदी पर 80 करोड़ रू. का विशेष लाभांश राज्य सरकार ने दिया है। वहीं केन्द्र सरकार ने खाद के अनुदान में कटौती करके खाद के मूल्यों में बहुगुणा वृद्धि करके किसानों को आहत किया है। केन्द्र सरकार की किसान विरोधी नीतियों पर हम चुप रहने वाले नहीं है। किसानों की लड़ाई सड़क से लेकर संसद तक लड़ी जायेगी और केन्द्र सरकार को रासायनिक खाद पर की गयी मूल्य वृद्धि वापस लेने के लिए विवश किया जायेगा।

श्री प्रभात झा ने डीएपी के मूल्यों में 141 प्रतिशत एनपी के मूल्यों में 158 प्रतिशत से 178 प्रतिशत और एमओपी पर 232 प्रतिशत मूल्य वृद्धि को किसान विरोधी बताते हुए कहा कि इससे किसानों की कमर टूट जायेगी। कृषि अर्थव्यवस्था मटियामेट हो जायेगी। भारतीय जनता पार्टी सरकार जहां खेती को लाभ के व्यवसाय में संवारने के लिए प्रयास कर रही है वहीं केन्द्र सरकार किसानों को तबाह करने पर आमादा है। परन्तु भारतीय जनता पार्टी कांग्रेसनीत यूपीए सरकार के इन तबाही के ओर ले जाने वाले मंसूबों को पूरा नहीं होने देगी। यह 'किसान बचाओ अनुष्ठान' केन्द्र सरकार को तंद्रा से जगायेगा और उसे किसानों के हित में सोचने में विवश होना पड़ेगा।

उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश के सभी 55 संगठनात्मक जिलों में 4 लाख से अधिक कार्यकर्ता और किसानों ने आज इस पावन अनुष्ठान में आहुतियां डाली हैं। हम इसके प्रतिफल के प्रति पूरी तरह आश्वस्त है। किसानों के हित में संघर्ष में किसानों की विजयी होगी। ■

गुजरात में वोट-बैंक की नहीं, विकास की राजनीति : नरेंद्र मोदी

&loknnkrk }kjk

Xजरात में डेढ़ दशक से अधिक समय से भाजपा की सरकार है। यहां विकास की नई इबारत लिखी जा रही है। विकास मानकों पर गुजरात देश में प्रथम क्रमांक पर है। यही कारण है कि गुजरात ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा। यह सब साकार हो सका है राज्य के लोकप्रिय और कुशल मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की जिजीविषा से। साल 2001 में भूकंप हुआ और 2002 में दंगा। पूरा प्रदेश आहत हुआ। लेकिन अपने कुशल प्रशासनिक क्षमता के बूते श्री मोदी ने गुजरात को कम ही समय में सशक्त किया। इसी के चलते उन्हें प्रदेश की जनता का असीम स्नेह मिला। यही कारण रहा कि उन्हें लगातार दो विधानसभा चुनावों में बहुमत का जनादेश मिला। कांग्रेस और छद्म पंथनिरपेक्षवादी इसे पचा नहीं पा रहे हैं और वे झूठे प्रपंच रचकर श्री मोदी को घेरने का षड्यंत्र कर रहे हैं लेकिन उन्हें हर बार मुंह की खानी पड़ रही है।

गत 9 एवं 10 जून 2012 को आत्मीय कॉलेज, कालावड रोड, राजकोट में भारतीय जनता पार्टी, गुजरात प्रदेश की दो दिवसीय कार्यकारिणी बैठक संपन्न हुई। बैठक में पार्टी ने तय किया गया कि केन्द्र सरकार की इस गुजरात विरोधी अन्यायकारी नीतियों के मुद्दे को लेकर पूरे राज्य में जनजागरण आंदोलन किया जाएगा।

प्रदेश कार्यकारिणी बैठक का उद्घाटन गुजरात प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री आर.सी. फलदु ने दीप–प्रज्जवलन कर किया। इस अवसर पर राज्य के मुख्यमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री पुरुषोत्तम रूपाला, राष्ट्रीय सह संगठन महासचिव श्री वी. सतीश जी के साथ प्रदेश पदाधिकारी, राज्य मंत्रिमंडल के कार्यकारिणी में अपेक्षित सदस्य उपस्थित रहे। बैठक में कांग्रेसनीत यूपीए सरकार द्वारा गुजरात के साथ किए जा रहे अन्याय और केन्द्र की दिशाविहीन भ्रष्ट सरकार की निष्फलता को उजागर करता हुआ प्रस्ताव कार्यकारिणी में रखा गया।

गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने समारोप–सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि केन्द्र की कांग्रेस शासित यूपीए सरकार ने उनके आठ साल के शासन में देश को ऐसे संकट में धकेल दिया है कि हिन्दुस्तान 21वीं सदी में शक्तिशाली सत्ता बनने की बजाय घोर निराशा में पड़ गया है। केन्द्र सरकार उनके भ्रष्ट राजनैतिक करतूत से ऐसी घिरी हुई है कि उसे बचने का कोई किनारा ही नहीं बचा। केन्द्र की कांग्रेस सरकार अब बचनेवाली नहीं है। ऐसे समय में गुजरात की विकास की राजनीति का मार्ग पूरे हिन्दुस्तान को दिशादर्शन करेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि गुजरात ने चुनाव लक्षी राजनीति को विकास की राजनीति का नया मोड़ देकर देश को रास्ता बताया है और अब सभी राजनीतिक पार्टियों को विकास की राजनीति को स्वीकार करना पड़ा है। गुजरात के पिछले दशक के तीनों सामान्य चुनाव में जनता ने भाजपा की वर्तमान सरकार को भव्य विजय दिलाया है और उत्तरोत्तर जनाधार बढ़ता रहा है।

उन्होंने बताया कि आज देश का नौजवान रोजगारी के लिए तरस रहा है, उनकी स्थिति दयनीय है। इस देश की गृहिणी के लिए महंगाई के इस समय में परिवार के लिए दो वक्त का खाना और जीना मुश्किल हो गया है। फिर भी केन्द्र की कांग्रेस शासित यूपीए सरकार महंगाई घटाने की बात तो दूर रही लेकिन महंगाई को रोकने में असमर्थ रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि रुपये की कीमत दिन–प्रतिदिन नीचे आकर डॉलर के मुकाबले में बिल्कुल गिर रही है उसका रहस्य क्या है? सिर्फ आर्थिक कारण नहीं है, भ्रष्ट राजनीति केन्द्र कर रही है, इसका यह नतीजा है। ऐसा बताते हुए उन्होंने कहा कि हिन्दुस्तान के अलावा पूरे एशिया खंड में आए हुए किसी भी देश की करंसी को ऐसी विपरीत स्थिति का सामना नहीं करना पड़ता है। सिर्फ हिन्दुस्तान का रूपया ही क्यों डॉलर के सामने गिर रहा है? देश के प्रधानमंत्री को इसका स्पष्ट जवाब देना चाहिए।

उन्होंने कहा कि गुजरात की भाजपा सरकार के सामने झूठ के षड्यंत्र की भरमार चल रही है, लेकिन कैसी भी आंधी आये, गुजरात उनकी विकास की राजनीति से विचलित नहीं होगा। यही एक रास्ता है जो युवा शक्ति के कौशल्य को रोजगारी की दिशा देता है, महिलाओं को सशक्तिकरण करता है, कृषि और ग्राम विकास से देश का अर्थतंत्र सशक्त होता है, पूरा एक दशक गुजरात ने ही सद्भावना की शक्ति से शांति, एकता एवं भाईचारा से देश की राजनीति को ऐसी ताकत दी है कि देश की घोर निराशा की स्थिति में गुजरात का विकास ही हिन्दुस्तान को नई दिशा दे सकती है ऐसी विश्वास गुजरात ने जताया है।

इससे पूर्व बैठक में प्रदेश अध्यक्ष श्री आर.सी. फलदु ने कहा कि गुजरात राज्य में मुख्यमंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी के नेतृत्व में कार्यरत भाजपा की सरकार के जनकल्याणार्थ कार्यक्रमों को प्रजा के बीच में ले जाने का कार्य कर अपना लक्ष्य साधना, यह समय की मांग है। भाजपा की सरकार एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय के स्वप्न को साकार करने हेतु कटिबद्ध है और अंत्योदय यानी कि समाज के पिछड़े हुए समाज के हित में कार्य कर रही है। जबकि कांग्रेस गरीब को सिर्फ मतदाता के रूप में देख रही है।

गुजरात विकास की राजनीति से विचलित नहीं होगा। यही एक रास्ता है जो युवा शक्ति के कौशल्य को रोजगारी की दिशा देता है, महिलाओं को सशक्तिकरण करता है, कृषि और ग्राम विकास से देश का अर्थतंत्र सशक्त होता है, पूरा एक दशक गुजरात ने ही सद्भावना की शक्ति से शांति, एकता एवं भाईचारा से देश की राजनीति को ऐसी ताकत दी है कि देश की घोर निराशा की स्थिति में गुजरात का विकास ही हिन्दुस्तान को नई दिशा दे सकता है।

भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री पुरुषोत्तम रूपाला ने कार्यकारिणी को संबोधित करते हुए बताया कि 2012 को गुजरात विधानसभा चुनाव राज्य और राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में अतिमहत्वपूर्ण है। उन्होंने अपनी आक्रामक शैली में कार्यकारिणी को संबोधित करते हुए बताया कि केन्द्र की कांग्रेस सरकार भ्रष्टाचार में मशगूल है। प्रजा त्राहिमाम है और कांग्रेस अपना जनाधार गंवा रही है। चुनाव के नतीजे कांग्रेस के विरुद्ध आ रहे हैं। भाजपा कार्यकर्ता कांग्रेस के भ्रष्टाचार के बारे में जनता को बताएं और समझाएं कि गुजरात से कांग्रेस को जड़मूल से उखाड़ फेंको।

बैठक में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं और गुजरात के समाज जीवन के अग्रणी महानुभावों के अवसान पर शोक प्रदर्शित करता हुआ प्रस्ताव पारित किया गया। 'राजनीतिक प्रस्ताव' प्रदेश महासचिव श्री शंकरभाई चौधरी ने रखा, जिसका अनु. जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्री डॉ. जीवराज चौहाण ने समर्थन किया। 'कृषि विकास में अग्रसर गुजरात' का प्रस्ताव प्रदेश उपाध्यक्ष श्री कौशिक भाई पटेल ने रखा, जिसका समर्थन प्रदेश महासचिव श्री भरतसिंह परमार ने किया।

प्रदेश कार्यकारिणी के दूसरे दिन के प्रारम्भ में भाजपा के प्रदेश महासचिव श्री विजय रूपाणी ने 'कांग्रेस हटाओ–देश बचाओ' की मांग करता महंगाई विरोध का प्रस्ताव प्रस्तुत किया, इस प्रस्ताव का भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती स्मृति इरानी ने समर्थन दिया।

भाजपा की दो दिन की कार्यकारिणी में उपस्थित राष्ट्रीय सह संगठन महासचिव श्री वी. सतीश ने कांग्रेस के नेतृत्व में कार्यरत यूपीए सरकार द्वारा देश की एकता और अखण्डता को तोड़ने की विघातक नीतियों का राष्ट्रभक्ति के रंग में रंगे हुए भाजपा के कार्यकर्ताओं को उनका मुकाबला करने के लिए कटिबद्ध रहने का आह्वान किया।

प्रदेश कार्यकारिणी में मुख्यमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में कार्यरत भाजपा सरकार के दस साल के विकास कार्यों की सराहना करते हुए 'दशक के विकास की बधाई' का प्रस्ताव प्रदेश उपाध्यक्ष एवं प्रदेश प्रवक्ता श्री आई.के. जाडेजा ने तथ्यों के साथ प्रस्तुत किया, जिसका समर्थन राज्यसभा सांसद मनसुख मांडवीया ने किया। ■

आंध्रप्रदेश उपचुनावों में कांग्रेस का सूपड़ा साफ मप्र में खिला कमल

loknnkrk }kjk

Xत 15 जून को आठ राज्यों के आए उपचुनावों के परिणामों से कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा। बेलगाम महंगाई और भ्रष्टाकचार से त्रस्त जनता ने कांग्रेस को अपने लोकतांत्रिक हथियार से सबक सिखाया।

आंध्र प्रदेश

आंध्र प्रदेश में जगनमोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली वाईएसआर कांग्रेस ने कांग्रेस को तगड़ा झटका देते हुए 15 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की। पार्टी ने नेल्लोर लोक सभा सीट भी भारी बहुमत से जीत ली। 10 सीटों पर कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई, हालांकि वह 2 सीट जीतने में कामयाब रही। तेलंगाना राष्ट्र समिति को 1 सीट मिली। गौरतलब है कि आंध्र में एक लोकसभा सीट और 18 विधानसभा सीटों पर 12 जून को उपचुनाव हुए थे।

मध्य प्रदेश

राज्यसभा की भाजपा सरकार पर जनता का अटूट भरोसा कायम है। महेश्वर उपचुनाव में भी कमल खिला। भाजपा के श्री राजकुमार मेव ने अपने प्रतिद्वंदी कांग्रेस के श्री देवेंद्र साधौ को 31776 मतों के भारी अंतर से हरा दिया। श्री मेव को जहां 85037 वोट मिले, वहीं श्री साधौ को 53271 मतों से संतोष करना पड़ा। 2013 में प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं इसलिए यह उपचुनाव कांग्रेस व भाजपा दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण माना जा रहा था। गत तीन वर्षों में यह पांचवां विधानसभा उपचुनाव (तेंदूखेड़ा, कुक्षी, सोनकच्छ, जबेरा और महेश्वर) है जिसमें कांग्रेस को भाजपा के हाथों अपने गढ़ में लगातार हार झेलनी पड़ी।

पश्चिम बंगाल

राज्य की बांकुड़ा और दासपुर सीटों पर तृणमूल कांग्रेस ने अपना कब्जा बरकरार रखा और माकपा को मात दी। बांकुड़ा से तृणमूल कांग्रेस की मिनाती मिश्रा ने माकपा के अपने प्रतिद्वंद्वी निलांजन दासगुप्ता को पंदह हजार वोटों के अंतर से हराया। दासपुर से तृणमूल कांग्रेस की ममता भुइयां ने माकपा के समर मुखर्जी को लगभग 19 हजार वोटों के अंतर से हराया। इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस ने आश्चर्यजनक रूप से उत्तर प्रदेश के माट सीट पर भी जीत दर्ज कर ली। पहले यह सीट राष्ट्रीय लोकदल के पास थी।

झारखंड

हटिया विधानसभा उपचुनाव में ऑल झारखंड स्टुडेंट यूनियन (आजसू) पार्टी के नवीन जायसवाल ने झारखंड विकास मोर्चा (झाविमो) के अजय नाथ साहदेव को 11,000 वोटों से शिकस्त देकर जीत का परचम लहराया। भाजपा तीसरे नंबर पर रही जबकि कांग्रेस चौथे पायदान पर।

महाराष्ट्र

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने महाराष्ट्र के केज विधानसभा सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखा। पार्टी के उम्मीदवार पृथ्वीराज साठे ने भाजपा की संगीता तोम्बधरे को हराया।

त्रिपुरा

त्रिपुरा की सत्तारूढ़ माकपा ने नलचर सीट को अपने पास बनाए रखा। पार्टी उम्मीदवार तपन चंद दास ने कांग्रेस उम्मीदवार द्विजेंदलाल मजूमदार को हराया।

तमिलनाडु

तमिलनाडु के पुडुकोट्टी सीट पर हुए उपचुनाव में एआईएडीएमके उम्मीदवार कार्तिक ने डीएमके उम्मीदवार जाहिर हुसैन को बुरी तरह पराजित

किया।

केरल

केरल में नेयात्तिंकारा विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस के आर. सेल्वाराज ने अपने निकटतम प्रतिद्वन्द्वी माकपा के एस. लॉरेंस को 6,334 वोटों से हराया।

कर्नाटक विधान परिषद चुनाव

भाजपा की शानदार जीत, कांग्रेस को झटका

गत 12 जून को कर्नाटक विधान परिषद के चुनावों में सत्तारुढ़ भारतीय जनता पार्टी ने शानदार सफलता प्राप्त की वहीं विपक्षी कांग्रेस को झटका लगा। इस चुनाव में कांग्रेस का एक उम्मीदवार हार गया जबकि भाजपा ने अपनी सभी 6 सीटों पर विजय हासिल कर ली।

विधान परिषद की 11 सीटों के लिए 12 उम्मीदवार मैदान में थे। भाजपा ने छह सीटों पर चुनाव लड़ा था जिनमें वह सभी पर विजयी रही। जनता दल (एस) ने एक उम्मीदवार उतारा था जो विजयी रहा जबकि कांग्रेस के तीन उम्मीदवार जीते। कांग्रेस के चौथे उम्मीदवार इकबाल अहमद सरदीगी हार गए। कांग्रेस के बागी और निर्दलीय बी सुरेश ने जद (एस) के सहयोग से जीत दर्ज की। ■

पंजाब नगर निकाय चुनाव में फिर अकाली-भाजपा का परचम

तीन माह पहले ही दुबारा सत्तारूढ़ हुई अकाली दल (बादल)–भारतीय जनता पार्टी गठबंधन ने नगर निकाय चुनाव में भी शानदार जीत दर्ज की। गठबंधन ने अमृतसर नगर निगम में 48, जालंधर में 30, पटियाला में 39 और लुधियाना में 39 सीटों पर शानदार जीत दर्ज कर चारों शहरों में अपने महापौर बनाने का मार्ग प्रशस्त किया। शहरी क्षेत्रों में अपने जनाधार का दावा करने वाली कांग्रेस का तो इन चुनावों में सूपड़ा ही साफ हो गया और अधिकांश स्थानों में वह नाक बचाने लायक सीटें भी नहीं जीत सकी।

अमृतसर के 65 वार्डों में अकाली दल (बादल)–भाजपा गठजोड़ ने 48 सीटों पर कब्जा जमाया जबकि कांग्रेस को मात्र 5 सीटों पर संतोष करना पड़ा। शेष अन्यों के खाते में गईं। जालंधर नगर के 60 वार्डों में अकाली–भाजपा गठबंधन को 30 और कांग्रेस को 22 सीटों पर जीत हासिल हुई। यहां मनप्रीत बादल की पंजाब पीपुल्स पार्टी ने राज्य में पहली बार कहीं खाता खोला। पटियाला नगर निगम के 50 वार्डों में अकाली–भाजपा गठजोड़ ने 39 और कांग्रेस ने मात्र 8 सीटों पर विजय हासिल की। यह क्षेत्र विदेश राज्य मंत्री श्रीमती परनीत कौर व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह का क्षेत्र है। राज्य की औद्योगिक राजधानी लुधियाना के 75 वार्डों में अकाली–भाजपा गठजोड़ ने 39 और कांग्रेस ने मात्र 19 सीटों पर सफलता हासिल की। यहां अन्यों ने भी 17 सीटों पर कब्जा जमाया। इसके अतिरिक्त राज्य की तीन नगर काउंसिलों धर्मकोट, माछीवाड़ा और बलाचौर में भी सत्तारूढ़ गठजोड़ सफल रहा। धर्मकोट नगर काउंसिल की तो सभी 13 सीटों पर सत्तारूढ़ गठजोड़ सफल रहा है। जगराओ के वार्ड नंबर 13 के उपचुनाव में भाजपा ने कांग्रेस को परास्त किया। सनौर नगर काउंसिल का उपचुनाव भी अकाली दल (बादल) ने जीता है। राज्य की 26 नगर पंचायतों, जिनमें खेमकरन, राजासांसी, गोराया, शाहकोट, बेगोवाल, ढिलवां, भुलत्थ, माहिलपुर, मलौद, साहनेवाल, मुल्लांपुरदाखा घग्गा, घन्नौर, दिड़बा, मुनक, खनौरी, हंडियाया, अमलोह, बाघापुराना, मक्खू, मल्लांवाला, तलवंडी साबो, बरीवाला, भीखी, चीमा, भोगपुर में भी अकाली–भाजपा गठजोड़ का कब्जा हो गया है। ■

गजल गायक मेहंदी हसन नहीं रहे

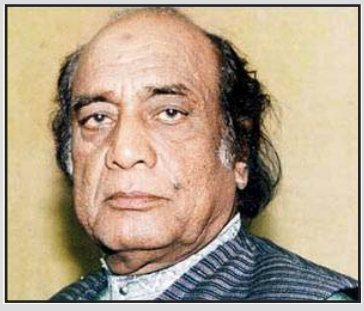

मशहूर गजल गायक मेहंदी हसन का 13 जून को देहांत हो गया। वह कराची के आगा खान अस्पताल में भर्ती थे, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। 84 वर्षीय मेहदी हसन पिछले 12 साल से बीमार चल रहे थे। वह फेंफड़ों में संक्रमण से पीडित थे। मेंहदी हसन का जन्म राजस्थान के झुंझुनूं जिले के लूणा गांव में 18 जुलाई 1927 को हुआ था। भारत–पाक बंटवारे के बाद उनका परिवार पाकिस्तान चला गया।

गजल के शहंशाह मेहंदी हसन के निधन पर गहरा दुःख व्यक्त करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी ने अपने शोक–संदेश में कहा कि मेहंदी हसन समूचे भारतीय उपमहाद्वीप में गजल गायिकी में विशिष्ट स्थान रखते थे। ■